सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

*"जो पल अभी है...वहीं सबसे कीमती है...
बीता हुआ कहानी है, आने वाला सपना है,
पर ये पल जीवन का सच है" ...!!*

अज्ञात...

वर्ष-01 अंक-68 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, रविवार 29 मार्च 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य -2 रुपए,

रिसॉर्ट में पका रहा था हिरण, वन विभाग की छापामार कार्रवाई-मैनेजर सहित 4 आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / बिलासपुर

जिले में वन्यजीव संरक्षण कानून की खुली अवहेलना का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पर्यटन क्षेत्र में संचालित एक रिसॉर्ट में हिरण के शिकार कर उसके मांस को पकाने की सूचना पर वन विभाग ने दबिश दी, जहां किचन में पकता हुआ मांस बरामद हुआ। इस मामले में रिसॉर्ट मैनेजर सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मामला बेलगहना वन परिक्षेत्र के कुरदर स्थित एथनिक रिसॉर्ट का है। वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां हिरण का शिकार कर मांस तैयार किया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर छापेमारी की, जहां कड़ाही में मांस पकता हुआ मिला। संदेह के आधार पर उसे जब्त कर लिया गया।

मैनेजर और कर्मचारियों के लिए बन रहा था मांस

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रिसॉर्ट में 8-10 कर्मचारी कार्यरत हैं और पकाया जा रहा मांस मैनेजर व स्टाफ के लिए तैयार किया जा रहा था। इस मामले में कुक रामकुमार टोप्पो, मैनेजर रजनीश सिंह, रमेश यादव और संजय वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

पूछताछ में एक-दूसरे पर डालते रहे जिम्मेदारी

पूछताछ के दौरान मैनेजर और कमर्चारियों ने मांस की जानकारी से अनभिज्ञता जताते हुए पूरा दोष कुक पर मढ़ दिया। वहीं कुक रामकुमार टोप्पो ने दावा किया कि उसे गांव के एक व्यक्ति जनक बैगा द्वारा पत्तों में लाकर मांस दिया गया था। फिलहाल सभी आरोपियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं।

जबलपुर लैब भेजा जाएगा सैंपल

वन विभाग ने जब्त मांस को जांच के लिए जबलपुर स्थित प्रयोगशाला भेजने की तैयारी की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मांस हिरण का ही है या नहीं। हालांकि, मौके से हिरण के अन्य अवशेष नहीं मिले हैं।

क्षेत्र में पहले भी हो चुके हैं शिकार के मामले

कोटा-बेलगहना क्षेत्र में वन्यजीवों के शिकार के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। जंगलों में करंट लगाकर बाघ, तेंदुआ और जंगली सूअरों का शिकार किए जाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। ताजा कार्रवाई के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में निगरानी और सख्त कर दी है।

वन्यजीव प्रेमियों में नाराजगी

गौरतलब है कि मामला प्रकाश आने के बाद वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश का वातावरण हैं। वन जीव प्रेमियों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों ने आरोप लगाया है कि यह पहली घटना नहीं है इसके पहले भी मांसभक्षी वन्यजीवों का कत्ल करते रहे हैं। पहली बार मामले का खुलासा हुआ है। अब देखना यह है कि वन विभाग और प्रशासन के लोग किस तरह से ठोस कदम उठाते हैं।

विशेष टिप्पणी

पहचान की जंग और घटता स्वाभिमान

आलोक तिवारी

भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026' के लागू होने के साथ ही पहचान की कानूनी प्रक्रिया में एक बुनियादी बदलाव सामने आया है। अब तक जो व्यवस्था 'स्व-घोषणा' Self-determination) पर आधारित थी, उसे अब मेडिकल बोर्ड की अनिवायर्ता से जोड़ दिया गया है। यह परिवर्तन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का बदलाव नहीं, बल्कि व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और आत्म-सम्मान से जुड़ा गंभीर प्रश्न है।

अब तक 2019 के कानून के तहत एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति शपथ पत्र के माध्यम से अपनी पहचान घोषित कर सकता था। यह व्यवस्था इस विचार पर आधारित थी कि लिंग केवल जैविक संरचना नहीं, बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत अनुभूति है—एक ऐसा अनुभव जिसे बाहरी परीक्षणों से पूरी तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता। दुनिया के कई देशों ने इसी सिद्धांत को स्वीकार करते हुए व्यक्ति के आत्म-निर्णय के अधिकार को प्राथमिकता दी है।

लेकिन नए संशोधन ने इस अधिकार को सीमित कर दिया है। अब पहचान के लिए मेडिकल बोर्ड की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई है, जो व्यक्ति की पहचान को गुणसूत्र, हार्मोन और शारीरिक संरचना के आधार पर तय करेगा। सवाल यह उठता है कि क्या विज्ञान किसी व्यक्ति के भीतर के अस्तित्व को माप सकता है? क्या कोई मेडिकल परीक्षण कर उस पहचान को प्रमाणित कर सकता है, जिसे व्यक्ति स्वयं जीता है?

यह व्यवस्था कई स्तरों पर चिंताजनक है। पहली बात, यह व्यक्ति की निजता और आत्मसम्मान पर सीधा प्रहार करती है। किसी को अपनी पहचान साबित करने के लिए बार-बार जांच और प्रमाण के दौर से गुजरना पड़े, यह अपने आप में अपमानजनक अनुभव हो सकता है। दूसरी बात, देश के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मेडिकल बोर्ड तक पहुंचना आसान नहीं होगा। इससे उनकी पहचान का अधिकार एक जटिल और लंबी प्रक्रिया में उलझ सकता है।

इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि भारत में लैंगिक विविधता कोई नई अवधारणा नहीं है। प्राचीन ग्रंथों और सांस्कृतिक प्रतीकों में इसकी स्पष्ट झलक मिलती है। इसके बावजूद आधुनिक समाज में इसे लेकर जो संकीणर्ता दिखाई देती है, वह अधिकतर औपनिवेशिक मानसिकता की देन है।

कानून का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को संरक्षण देना होता है, न कि उन्हें और अधिक जटिल प्रक्रियाओं में उलझाना। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने जिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा को मान्यता दी थी, यह संशोधन उस दिशा से एक कदम पीछे जाता हुआ प्रतीत होता है।

अंततः यह समझना आवश्यक है कि पहचान कोई दस्तावेज नहीं, बल्कि व्यक्ति का अस्तित्व है। इसे किसी प्रमाणपत्र या मेडिकल रिपोर्ट तक सीमित नहीं किया जा सकता। समाज और सरकार, दोनों को यह स्वीकार करना होगा कि वास्तविक सम्मान नियमों से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और स्वीकायर्ता से आता है।

पश्चिम एशिया की परिस्थितियों पर सीएम की उच्चस्तरीय समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कमिश्नर, आईजी व कलेक्टरों को निर्देश

पेट्रोलियम, गैस और उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता—अफवाहों से दूर रहने की अपील

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पश्चिम एशिया में उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी गैस, उर्वरकों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और संवेदनशील नेतृत्व के कारण कोविड जैसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी देश एकजुट रहा और सफलतापूर्वक उसका सामना किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वतर्मान में कोविड जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन सतर्क रहना आवश्यक है। प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों, गैस सिलेंडरों और उर्वरकों की कोई कमी नहीं है, अतः नागरिक किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम एशिया संकट पर सभी राज्यों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है और यह आश्वस्त किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है तथा उच्च स्तरीय समिति द्वारा स्थिति की सतत निगरानी की जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए तथा प्रभारी सचिव और कलेक्टर नियमित समीक्षा करें। अफवाहों और भ्रामक खबरों से बचने के लिए आमजन तक समय पर तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी या जमाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सभी पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों के भंडारण एवं आपूर्ति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।उन्होंने अधिकारियों से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए हर परिस्थिति में आमजन तक सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश में गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। गैस सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग सामान्य रूप से संचालित है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 45 दिन तथा सामान्य गैस कनेक्शन के लिए 25 दिन की समय सीमा निर्धारित है और वर्तमान में उसी अंतराल के अनुसार बुकिंग की जा रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन में भी किसी प्रकार की बाधा नहीं है और पूरे प्रदेश में स्थिति सामान्य है।

मुख्य सचिव विकास शील ने बताया कि वतर्मान परिस्थितियों की सतत निगरानी के लिए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उपभोक्ता घरेलू गैस आपूर्ति से संबंधित समस्याओं, शिकायतों अथवा कालाबाजारी की सूचना 1800-233-3663 पर दे सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि उक्त नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आमजन को सही जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके और शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में निर्देश दिए गए कि गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति से संबंधित समाचारों पर सतत निगरानी रखी जाए। भ्रामक खबरों से भय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अतः ऐसी खबरों का तत्काल संज्ञान लेकर वास्तविक जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए। सोशल मीडिया की भी विशेष निगरानी रखने और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

महत्वपूर्ण संस्थानों में गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री साय ने अस्पतालों, छात्रावासों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे, भारत सरकार की संस्थाओं, सैन्य एवं अधर्सैनिक बलों, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थानों और एयरपोर्ट कैंटीनों में गैस आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के निर्देश दिए।

कार्रवाई-3841 सिलेंडर जब्त, 97 एफआईआर हुई दर्ज

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेशभर में 335 स्थलों पर छापेमारी की गई, जिसमें कालाबाजारी की कोई पुष्टि नहीं हुई। हालांकि जमाखोरी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3841 गैस सिलेंडरों को जब्त किया गया तथा 97 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सीमावर्ती चेक पोस्टों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। गैस सिलेंडरों एवं पेट्रोल-डीजल वाहनों की आवाजाही पर निगरानी रखने के साथ ही निर्देश दिए गए कि पेट्रोल-डीजल को कंटेनरों में आम जनता को उपलब्ध न कराया जाए। केवल अधिकृत मोबाइल टावर एवं जेनसेट संचालित आवश्यक प्रतिष्ठानों को ही कंटेनर में ईंधन उपलब्ध कराया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्त, आईजी एवं जिला कलेक्टर भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार सहित आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के पेट्रोल, डीजल एवं गैस डिवीजन के अधिकारी उपस्थित थे।

उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, समय पर मिलेगा खाद

वीडियो कांफ्रेंस के दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उर्वरकों की होल्डिंग पर रोक लगाई जाए और दैनिक स्टॉक की नियमित समीक्षा की जाए। सभी किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समान रूप से उर्वरक उपलब्ध कराया जाए।साथ ही खाद वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर आधारित मॉनिटरिंग की जानकारी भी साझा की गई।

गैस संकट पर 'ठोस' निर्णय के बजाय सिर्फ औपचारिकता

पश्चिम एशियाई संकट के बीच प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा ली गई हाई-प्रोफाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) महज एक प्रशासनिक खानापूर्ति भर होती दिख रही है। राज्य के उद्योगों, शिक्षण संस्थानों और आम जनता से जुड़े 'ज्वलंत' मुद्दों पर न तो किसी IAS-IPS अधिकारी ने कोई कायर्योजना पेश की और न ही सरकार की ओर से कोई साहसिक निर्णय लिया गया।

उद्योग और हॉस्टल राम भरोसे : निजी कंपनियों की चांदी

बैठक में सबसे बड़ी अनदेखी उन उद्योगों, स्कूलों और हॉस्टलों की हुई, जहाँ महीने में 50-60 से लेकर 150-200 कॉमर्शियल सिलेंडरों की खपत है। आपूर्ति सीमित होने से इन संस्थानों के कामकाज ठप होने की कगार पर हैं। आश्चर्यजनक है कि गैर सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) के स्टॉक पर चुप्पी साध ली गई, जबकि इन्हीं निजी गैस कंपनियां 'आपदा में अवसर' तलाशते हुए दोगुने-तिगुने दामों पर

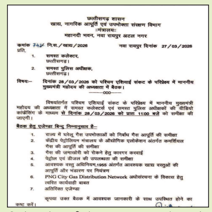
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 742 नि.स./खाद्य/2026 नवा रायपुर दिनांक 27/03/2026

प्रति,
1. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
2. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़।

विषयः- दिनांक 28/03/2026 को पश्चिम एशियाई संकट के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में बैठक।

---000---

विषयांतर्गत पश्चिम एशियाई संकट के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में समस्त कलेक्टर्स एवं समस्त पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 28/03/2026 को प्रातः 11:00 बजे को समीक्षा की जाएगी।

बैठक हेतु एजेण्डा बिन्दु निम्नानुसार है-
1. राज्य में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को निर्बाध गैस आपूर्ति की समीक्षा
2. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के औद्योगिक एलोकेशन अंतर्गत कमर्शियल गैस की आपूर्ति की समीक्षा
3. गैस की जमाखोरी को रोकने हेतु कारगर करवाई
4. पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता की समीक्षा
5. आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 अंतर्गत आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति और भंडारण पर नियंत्रण
6. PNG City Gas Distribution Network अधोसंरचना के विकास हेतु त्वरित कार्यवाही बाबत
7. अतिरिक्त एजेण्डा

कृपया उक्त बैठक में आवश्यक जानकारी के साथ उपस्थित होने का कष्ट करें।

सिलेंडर बेच रही हैं। क्या सरकार और उनके अधिकारियों की फौज को यह नजर नहीं आता कि निजी सप्लायर्स को कालाबाजारी की खुली छूट क्यों मिली हुई है?

सामाजिक आयोजनों पर संकट : एजेंडे से गायब रही जनता की जरूरत

शादी-ब्याह, मृत्यु भोज और भंडारों जैसे अति-आवश्यक सामाजिक कार्यक्रमों के लिए गैस की भारी किल्लत है। वितरक (Distributors) जनता के आक्रोश का सामना कर रहे हैं, लेकिन बैठक के मुख्य एजेंडे में इस विषय को जगह ही नहीं दी गई। सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री को जमीनी हकीकत से दूर रखा गया या अफसरों ने इस संवेदनशील मुद्दे को जानबूझकर नजरअंदाज किया।

DAC की तकनीकी पेचीदगी पर प्रशासन का मौन

भारत सरकार की DAC (डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड) व्यवस्था आम उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द बनी हुई है। पुराने अंतराल के कारण कोड नही मिलना और तकनीकी अज्ञानता के चलते वितरण केंद्रों पर रोज विवाद हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में तेल कंपनियों से इस व्यवस्था में सुधार पर कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं की गई। ऐसा प्रतीत होता है मानो उपस्थित टीम को आम जनता की इस दैनिक समस्या से कोई सरोकार ही नहीं रहा है।

VIP कल्चर के आगे नियम नतमस्तक : आखिर कब लगेगा अंकुश?

वितरण प्रणाली में सबसे बड़ी बाधा 'वीआईपी' वर्ग बना हुआ है। नेता, पार्षद, जज और पुलिस के आला अधिकारी DAC कोड साझा करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। वितरकों के डिलीवरी बॉयज को इन रसूखदारों के कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है।

सवाल : मुख्यमंत्री ने इस बैठक में सार्वजनिक रूप से यह क्यों नहीं कहा कि नियम सभी के लिए समान हैं?

सवाल : क्या अधिकारियों और नेताओं को नियमों का पालन करने के लिए कोई स्पष्ट निर्देश या खाका तैयार नहीं किया जाना चाहिए था?

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में खिंची गई सरकारी लकीरें जनता की समस्याओं को हल करने में नाकाम दिख रही हैं। जब तक 'सामानांतर' निजी कंपनियों की मनमानी पर लगाम और वीआईपी कल्चर पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक ऐसी बैठकों का कोई जनहितकारी परिणाम निकलना मुश्किल है।

कार चढ़ाकर हत्या की कोशिश मची खलबली, आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग-जामुल

जामुल थाना क्षेत्र में देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक आरोपी ने न केवल कई वाहनों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, बल्कि एक व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से उस पर कार चढ़ाने का प्रयास भी किया। पुलिस की त्वरित कारर्वाई से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 28 मार्च की रात करीब 2:30 बजे Amrapali Vananchal City में हुई। प्रार्थी मंजीत सिंह ने थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी लखन साहू ने उनकी स्कॉपियो (CG 04 NR 9009) को चालू कर कॉलोनी में खड़ी अन्य गाड़ियों को टक्कर मारते हुए 5-6 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। जब प्रार्थी मौके पर पहुंचकर आरोपी को रोकने का प्रयास कर रहा था, तब आरोपी ने उस पर कार चढ़ाकर हत्या करने की कोशिश की। हालांकि प्रार्थी समय रहते हट गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

घटना के बाद थाना जामुल में अपराध क्रमांक 192/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लखन साहू (55 वर्ष), निवासी कुरूद रोड कोहका, भिलाई, ने आक्रोश और असामाजिक प्रवृत्ति के चलते इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त कर लिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।

भिलाई में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत, सामाजिक कार्यों की मिली सराहना

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भारतीय जनता युवा मोर्चा, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा के भिलाई आगमन पर कोहका स्थित सर्व समाज कल्याण समिति कार्यालय में उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू सहित पदाधिकारियों ने उन्हें संस्था द्वारा किए जा रहे विभिन्न सामाजिक एवं जनकल्याणकारी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी।

इंद्रजीत सिंह छोटू ने दी जानकारी, महिला सशक्तिकरण को भी दिया बढ़ावा

समिति की ओर से अतिथि के सम्मान में मोमेंटो भेंट कर आभार प्रकट किया गया। इस दौरान सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए आगे भी जनहित में कार्य जारी रखने की बात कही गई।

वहीं कबीर वाटिका, बजरंग पारा कोहका में इंद्रजीत सिंह छोटू ने बहनों से आत्मीय मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान महिलाओं ने स्वावलंबन की दिशा में चल रहे सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण की जानकारी साझा की। महिलाओं के उत्साह और आत्मनिर्भर बनने के जज्बे की सराहना करते हुए उन्हें हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया गया।

सामाजिक सरोकार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह पहल क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रही है। इस अवसर पर मलकीत सिंह जोगा राव सहित परिवार इंद्र के सदस्य मौजूद थे

शीतला मंदिर में जोत जंवारा विसर्जन शोभायात्रा के दौरान बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

कसारीडीह सिविललाइन स्थित मां सतरूपा शीतला मंदिर में चैत्र नवरात्र का पर्व पूरे आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया गया। रामनवमी और चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन शुक्रवार को मंदिर समिति द्वारा जोत जंवारा की भव्य विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में महिलाएं एक रंग के वेशभूषा में शामिल हुए, जो आकर्षण का केन्द्र बना रहा, वहीं महिलाएं जस गीत की धुन में झूमते हुए अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करते रहे। जिससे पूरे शोभायात्रा के दौरान श्रद्धा-भक्ति का अद्भुत माहौल बना। यह शोभायात्रा मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए शीतला तालाब पहुंची। जहां जोत जंवारा का विसर्जन किया गया। ज्योत जंवारा के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़े।

भायात्रा के समापन उपरांत महाभंडारा का आयोजन किया गया। महाभंडारा में प्रसादी ग्रहण कर श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ प्राप्त किया। ज्योत जंवारा विसर्जन शोभायात्रा के दौरान सतरुपा शीतला सेवा समिति के अध्यक्ष रोमनाथ साहू, उपाध्यक्ष शिवसागर सिन्हा, सचिव प्रदीप देशमुख, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र धर्माकर, सह-सचिव चंपा साहू, कायर्कारिणी सदस्य तामेश्वर यादव, पुष्पा श्रीवास, संरक्षक भीखम साहू, कृष्णा देशमुख, गणेश निर्मलकर, राजा सिंह राजपूत, राजेश साहू, दीनानाथ निर्मलकर, धनेश सिंह राजपूत, राजेंद्र सिंह चंदेल, नरेश कुटारे, ईश्वर अग्रवाल, भाजपा नेता विनोद चंद्राकर, पूर्व पार्षद कांता साहू, धनेन्द्र सिंह चंदेल, किशोर यादव, अभय तिवारी, संजय डहरवाल, संतोष यादव, श्रीधर भजने, निशा ठाकुर, गणेशराम चौधरी, तोरण साहू, अरुण साहू, अदिति खरिया, राखी, लेखिका अडिया, रानी उपाध्याय, आरती शुक्ला के अलावा सतरुपा शीतला सेवा समिति के अन्य सदस्य व श्रद्धालु व्यवस्था बनाने में जुटे रहे।

जसगीत की धुन में झूमरती टोली

हिन्दू नववर्ष के पहले दिन से शुरू होने वाला चैत्र नवरात्रि में आस्था विश्वास के साथ भक्ति में डूबे डुंडेरा में जसगीत की धुन में झूमरती टोली के साथ पांच घरों से निकले जंवारा विसर्जन को देखने लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। जंवारा को विसर्जन के पहले गांव में स्थित मां शीतला मंदिर और महा तेजेश्वर महादेव मंदिर की परिक्रमा करने के बाद तालाब में विसर्जित किया गया। इस पर्व में महत्वपूर्ण योगदान नवयुवा जागरण मां शीतला सेवा समिति का रहता है। इस बार भी समिति के सदस्यों ने सेवा भाव से अपने कर्तव्य को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

खास खबर

करदाता जल्द से जल्द करें भुगतान, पेनल्टी से बचे निगम प्रशासन ने बढ़ाई सुविधाएं

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा शहर के समस्त करदाताओं को कहा गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व संपत्ति कर व अन्य कर निगम में जमा करने के लिए अब केवल अंतिम 4 दिन शेष रह गए हैं। निगम प्रशासन द्वारा करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत नगर निगम परिसर के टैक्स निरंतर शनिवार-रविवार खुले रखे जा रहे हैं, ताकि नागरिक बिना किसी असुविधा के अपना कर जमा कर सकें।

निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कर संग्रहण को सुचारू एवं व्यवस्थित बनाने के लिए अतिरिक्त कमर्चारियों की ड्यूटी लगाई गई है तथा काउंटरों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। नागरिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए समय-समय पर व्यवस्था का निरीक्षण भी किया जा रहा है, जिससे करदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

आयुक्त ने शहर के समस्त करदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और शीघ्र ही अपने बकाया कर का भुगतान कर दें। समय सीमा के भीतर कर जमा करने से करदाता अनावश्यक पेनल्टी एवं फाइन से बच सकते हैं, वहीं अंतिम तिथि के पश्चात निगम द्वारा नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें जुर्माना, अधिभार एवं अन्य विधिक कार्यवाही शामिल हो सकती है। करदाताओं से आग्रह की अपना टैक्स ऑनलाइन घर बैठे https://municipalcorporation.in/ जमा कर सकते है। प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह समय पर कर जमा कर शहर के विकास में सहभागी बने। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा सभी करदाताओं से आग्रह किया गया है कि वे निगम कार्यालय पहुंचकर या उपलब्ध माध्यमों के जरिए शीघ्र कर जमा करें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें।

मंत्री यादव ने किया सहकारी बैंक दुर्ग प्रधान कार्यालय नया भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के प्रधान कार्यालय भवन के निर्माण कार्य प्रारंभ पूजन कार्यक्रम गजेन्द्र यादव मंत्री स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधी एवं विधायी कार्य छग शासन रायपुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रीतपाल बेलचंदन अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग ने किया।

कार्यक्रम में श्रीमती अल्का बधमार महापौर नगर पालिक निगम दुर्ग, सुरेन्द्र कौशिक, अध्यक्ष, जिला भाजपा दुर्ग, नरेश यदु , उपाध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग, शिव चन्द्राकर, प्रदेश संयोजक, आर्थिक प्रकोष्ठ, भाजपा, रमाकांत द्विवेदी, पूर्व संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. दुर्ग, टिकाराम साहू पूर्व अध्यक्ष, जिला सहकारी संघ मर्या. दुर्ग श्रीमती खिलेश्वरी देवांगन अध्यक्ष जनपद पंचायत दुर्ग, पवन शर्मा उपाध्यक्ष जिला पंचायत दुर्ग, दिलीप साहू जिला भाजपा महामंत्री, शिवेन्द्र परिहार उपाध्यक्ष जिला भाजपा दुर्ग, सजान जोसेफ प्रदेश महामन्त्री अल्पसंख्यक मोर्चा, श्यामलाल साहू दुर्ग जिला सहकारिता प्रकोष्ठ संयोजक, मनोज अग्रवाल वरिष्ठ भाजपा नेता, हिमांशु सिंह दुर्ग भाजयुमो अध्यक्ष, टेकन सिन्हा, दुर्ग अन्य पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष, अजय तिवारी, देवनारायण चन्द्राकर, सुरेन्द्र बजाज, वरिष्ठ भाजपा नेता, एस. के. वर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भट्टाचार्य कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग दुर्ग उपस्थिति रहें। स्वागत उद्बोधन में एसके वर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि 11 महिने में 2.77 करोड़ की लागत से तीन मंजिला भव्य भवन शीघ्र निर्मित होगा।

प्रीतपाल बेलचंदन ने अपने उद्बोधन में कहा कि सहकारिता किसानों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए है और इसी क्रम में बैंक मुख्यालय के नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भपूजन अत्यंत हर्ष का विषय है। उन्होने अत्यंत कम समय में मंत्री द्वारा बैंक आगमन के लिए समय देने पर धन्यवाद ज्ञापित किया।

मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर सहकारी बैंक दुर्ग के मुख्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ पूजन अवसर पर बैंक के पदाधिकारियों अधिकारियों एवं किसानों को शुभकामनाएँ दी। सहकारिता के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं सहित भवन का निर्माण होने से किसानों को सुविधाएँ मिलेंगी। आने वाले समय में ग्रामोद्योग एवं सहकारिता मिलकर कार्य करेंगे तथा समितियों के भण्डारण क्षमता में वृद्धि के लिए संयुक्त रुप से प्रयास करेंगे।

कार्यक्रम में सुरेन्द्र कौशिक जिला भाजपा अध्यक्ष, शिव चन्द्राकर, प्रदेश संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ भाजपा, ने संबोधित किया कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन नरेश यदु उपाध्यक्ष सहकारी बैंक एवं मंच संचालन हृदेश शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बैंक अधिकारी सुश्री कुसुम ठाकुर, के. के. नायक अधीक्षक, धीरेन्द्र देवांगन, शाखा प्रबंधक, सहित भाजपा के जिला व प्रदेश के पदाधिकारी व दुर्ग जिला से सभी मण्डल अध्यक्षगण एवं सेवा कारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित रहे।

बकायादारों पर निगम की सख्ती नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नगर पालिक निगम दुर्ग के आयुक्त सुमित अग्रवाल के सख्त निर्देशों के बाद राजस्व अधिकारी आरके बोरकर के मार्गदर्शन में निगम का राजस्व विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लंबे समय से बकाया कर राशि जमा नहीं करने वाले करदाताओं के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। निगम प्रशासन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसी क्रम में आज राजस्व विभाग की टीम, सहायक राजस्व अधिकारी थानसिंह यादव, राजस्व उप निरीक्षक संजय मिश्रा, उद्यान प्रभारी अनिल सिंह, अतिक्रमण प्रभारी परमेश्वर कुमार,खिलावन शर्मा, नितिन श्रीवास के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 49 में पहुंची, जहां बकायादार जे.एन. मेहता के यहां 46,510 रुपये एवं आर. एस. कोचर 1,04272 रूपये की बकाया राशि लंबे समय से जमा नहीं किए जाने पर नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई।

इस कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने अन्य बकायादारों को भी सख्त चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही बकाया राशि जमा नहीं की गई तो इसी प्रकार की कार्र्वाई आगे भी जारी रहेगी।

आयुक्त सुमित अग्रवाल ने शहर के सभी करदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वे निगम के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और समय पर करों का भुगतान करें। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा लगातार समझाइश और सूचना देने के बावजूद यदि बकाया जमा नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है।

वाहन किराया के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, गिरवी रखे 9 चारपहिया वाहन व बाइक जप्त

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

थाना मोहन नगर क्षेत्र में वाहन किराये के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। आरोपियों के कब्जे एवं उनके द्वारा गिरवी रखे गए कुल 09 चारपहिया वाहन एवं 01 मोटरसाइकिल जप्त किए गए हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी आकुब खान की शिकायत पर थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 221/2026 के तहत धारा 318(4), 316(5), 3(5) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी माँ लक्ष्मी टूर एण्ड ट्रेवल्स के नाम से लोगों से वाहन किराये पर लेते थे, लेकिन वाहन मालिकों को किराया भुगतान नहीं करते थे। इसके बाद वे वाहनों को अन्य व्यक्तियों के पास गिरवी रख देते थे।

मोहन नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अमित कुमार सिंह (28 वर्ष), निवासी चारभाटा, जिला राजनांदगांव वरुण सलामे (25 वर्ष), निवासी डोंगरगढ़ को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया है। आरोपियों से जप्त वाहनों में महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, सुजुकी अटिर्गा, स्विफ्ट, टाटा पंच, वरना, बलेनो सहित कुल 10 वाहन शामिल हैं। साथ ही एक बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।

आरोपी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से लोगों को झांसे में लेकर वाहन किराये पर लेते थे और फिर भुगतान किए बिना वाहनों को गिरवी रख देते थे। थाना मोहन नगर पुलिस की सक्रियता से इस गिरोह का खुलासा हुआ और बड़ी संख्या में वाहन बरामद किए गए, जिससे वाहन मालिकों को राहत मिली है। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वाहन किराये पर देने से पहले संबंधित व्यक्ति या संस्था का सत्यापन अवश्य करें और बिना वैध दस्तावेज के वाहन न दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

जिले को पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में प्रदेश में मिला पहला स्थान

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन में दुर्ग जिले ने प्रदेश स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। राज्य कार्यालय द्वारा 26 मार्च 2026 को जारी रैंकिंग में जिले का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है।

जारी आंकड़ों के अनुसार जिले में 93.3 प्रतिशत आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 94.1 प्रतिशत हितग्राहियों को द्वितीय किस्त जारी की गई है, जबकि 81.4 प्रतिशत आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। मनरेगा मजदूरी भुगतान में भी दुर्ग जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 89.2 प्रतिशत (औसत 89.5 प्रतिशत) के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशन और जिला पंचायत के मुख्य कायर्पालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन में योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद पंचायत धमधा में 95, दुर्ग में 65 और पाटन में 31 हितग्राहियों को तृतीय किस्त की राशि जारी की गई है। इसके लिए 116 लाख रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है।

इसके अलावा 586 हितग्राहियों के लिए 259 लाख रुपए से अधिक की राशि एफटीओ के माध्यम से हस्तांतरण हेतु तैयार की गई है, जो जल्द ही उनके खातों में जमा होगी।

जिले में आवास निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाते हुए हर सप्ताह 80 से अधिक नए आवास शुरू किए जा रहे हैं और 200 से अधिक आवास पूर्ण किए जा रहे हैं। फरवरी माह में 831 आवास पूर्ण करने के लक्ष्य के मुकाबले 852 आवास पूर्ण कर जिले ने लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की है। निरंतर राशि हस्तांतरण से हितग्राहियों में उत्साह बढ़ा है, जिससे वे अपने घरों का निर्माण तेजी से पूरा कर रहे हैं।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में बालिकाओं को दिया व्यवसायिक प्रशिक्षण

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी आर के जामुलकर एवं जिला महिला बाल विकास अधिकारी अजय साहू के मार्गदर्शन में एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग ग्रामीण के द्वारा शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं का तीन दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम अलंकार मेकअप स्टूडियो एवं एकेडमी सेक्टर 7 प्रशिक्षक गगनदीप द्वारा किया गया। दुर्ग ग्रामीण परियोजना अधिकारी श्रीमती उषा झा ने बताया कि किशोरी बालिका प्रशिक्षण के अंतर्गत 25 किशोरी बालिकाओं को उनके आर्थिक सशक्तिकरण हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से ये किशोरी बालिकाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी।
इस व्यावसायिक प्रशिक्षण अंतर्गत इन किशोरी बालिकाओं को ब्यूटी पार्लर कोर्स का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें थ्रेडिंग वैक्स फैसियल हेयर कटिंग हेयर स्पा हेयर केमिकल ब्राइडल मेकअप पार्टी मेकअप हल्दी लुक इंगेजमेंट लुक पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में दुर्ग ग्रामीण परियोजना के विभिन्न सेक्टर से बालिकाएं उपस्थित रही। शशी पटेल डाकेश्वरी पटेल खुशबू साहू केसरी पटेल माधुरी राजपूत मानसी निषाद राधिका यादव तृप्ति कुंभकार नेहा कुर्रे भावना सिन्हा गायत्री बिंदा यादव डामेश्वरी यादव पुष्पा मंडावी मनीषा खुटेल सानिया खुटेल विपाशा कुर्रे चंचल कुर्रे नंदिनी दिनेश्वरी यादव बेबी यादव मनीषा यादव अक्षरा खुशी पटेल कुंती इस प्रकार 25 किशोरी बालिकाओं को ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण में इन बालिकाओं को चाय नाश्ता भोजन एवं यात्रा देयक दिया गया तथा प्रशिक्षण उपरांत सभी बालिकाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई।

गर्मी में राहगीरों के लिए जिला स्काउट संघ ने खोला प्याऊ घर

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

"प्रतिदिन एक अच्छा काम करो" के नेक विचार को आत्मसात करते हुए भिलाई जिला संघ स्काउट-गाइड की ओर से राहगीरों के लिए प्याऊ घर की व्यवस्था की गई। उल्लेखनीय है कि स्काउट गाइड जिला भिलाई एवं बीएसपी शिक्षा विभाग के नेतृत्व में वर्ष भर स्काउट गाइड की ओर से गतिविधियों जारी रहती है।

जिसमें समय-समय पर पर्यावरण संरक्षण एवं महापुरुषों की जन्म एवं पुण्यतिथियों को श्रद्धा पूर्वक मनाया जाना भी शामिल है। भिलाई विद्यालय सेक्टर-2 के मुख्यद्वार पर प्याऊ उद्घाटन के दौरान विद्यार्थी,पालक एवं बीएसपी शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारीगण उपस्थित थे। इनमें महाप्रबंधक एवं जिला मुख्य आयुक्त शिखा दुबे, जिला आयुक्त स्काउट एवं प्राचार्य भिलाई विद्यालय विजय सिंह पवार, कोषाध्यक्ष उवर्शी साहू, सचिव सरिता शाक्य, डीओसी कीर्तिलता देशमुख , एस.एन. साहू, वरिष्ठ व्याख्याता पवन अग्रवाल, डीके. साहू, डीटीसी डा. शीतलचंद्र शर्मा, अविनाश चंद्र शील एवं समस्त शिक्षकगण उपस्थित थे।

बेटियों के सम्मान का संकल्प : 240 नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री ने दिया सुखद दांपत्य जीवन का आशीर्वाद

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर के रणजीता स्टेडियम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए, जहां 240 नवविवाहित जोड़ों का विवाह विधिवत सम्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री श्री साय विवाह मंडप में पहुंचकर नवदंपतियों के बीच गए और उन्हें शुभाशीष प्रदान करते हुए उनके सुखद, समृद्ध एवं मंगलमय दांपत्य जीवन की कामना की। कार्यक्रम का वातावरण पारंपरिक रीति-रिवाजों, वैदिक मंत्रोच्चार और सामाजिक एकता के भाव से ओतप्रोत रहा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर उभरी है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग प्रदान कर उनके माता-पिता के आर्थिक बोझ को कम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने के साथ ही समाज में एकता और समरसता

को भी बढ़ावा देते हैं।

उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से हजारों परिवारों को राहत मिली है और बेटियों के विवाह को लेकर उनकी चिंता काफी हद तक दूर हुई है। सामूहिक कन्या विवाह समारोह में विभिन्न समाजों के 240 जोड़ों ने एक साथ विवाह कर सामाजिक समरसता और एकता का संदेश दिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को कुल 50 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 35 हजार रुपए की राशि चेक के माध्यम से सीधे हितग्राही को दी जाती है, जबकि लगभग 7 हजार रुपए की वैवाहिक सामग्री एवं 8 हजार रुपए आयोजन व्यय के रूप में खर्च किए जाते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने नवदंपतियों को 35 हजार रुपए की राशि के चेक वितरित किए और उनके खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना की।

सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गायत्री परिवार के सदस्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान से विवाह सम्पन्न कराया गया। कार्यक्रम में नवदंपतियों को विवाह प्रमाण पत्र एवं उपहार सामग्री भी प्रदान की गई। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दीं और योजना की सराहना की। यह आयोजन न केवल एक सामाजिक कार्यक्रम रहा, बल्कि शासन की जनकल्याणकारी सोच और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता का भी प्रतीक बना।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष रामप्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, जनपद पंचायत अध्यक्ष जशपुर गंगाराम भगत, विजय आदित्य सिंह जूदेव, सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह, वनमंडलाधिकारी शशिकुमार, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं गणमान्यजन उपस्थित थे।

खास खबर

स्वास्थ्य विभाग के प्रति नियुक्ति पदस्थापना में भ्रष्टाचार - कांग्रेस

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने पिछले सप्ताह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी प्रति नियुक्ति पदस्थापना के आदेश की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि इससे पूरे स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक अफरा तफरी मच जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे वसूली की एक और खिड़की खुलने की पूरी संभावना है। यह आदेश भ्रष्टाचार के उद्देश्य से निकाला गया प्रतीत होता है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने प्रशासनिक गरिमा और परंपराओं के पालन करने की सलाह देते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मांग किया है कि स्वास्थ्य विभाग के सभी पदों पर पिछले ढाई वषी से प्रमोशन नहीं हुए हैं सभी विभागों में समयबद्ध प्रमोशन किए जाने चाहिए और सभी स्वीकृत पदों को पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत भर्ती की जाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य विभाग का काम राजधानी और सुदूर जिलों में सुचारू ढंग से चल सके।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा है कि वर्तमान में डॉक्टर, चिकित्सा शिक्षकों, नर्सिंग पैरामेडिकल वर्कर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती नहीं हो पाने के कारण व्यवस्था पूरी तरह चौतरफा लकवे का शिकार हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार में स्वास्थ्य विभाग में प्रति नियुक्तियों का खेल जारी है।जिसके कारण निचले स्तर के कमर्चारी भी प्रति नियुक्ति उप संचालक बने बैठे हैं।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता ने राज्य के मुख्य सचिव विकासशील एवं स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को एक मेल भेज कर इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में जिला स्तर से प्रतिनियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे जाने को प्रक्रिया को तुरंत स्थगित करने की मांग की।

आज सामूहिक उपनयन संस्कार, 37 बटुक होंगे शामिल

रायपुर। कान्यकुब्ज सभा-शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा 29 मार्च को बैरन बाजार स्थित आशीर्वाद भवन में सर्व ब्राह्मण समाज के बटुकों के लिए सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन वैदिक रीति-रिवाजों के साथ विद्वान आचार्यों के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। संस्था के अध्यक्ष सुरेश मिश्रा और सचिव राजकुमार दीक्षित ने बताया कि इस संस्कार में प्रदेश के विभिन्न जिलों—रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, बिलासपुर, बलौदा बाजार, भाटापारा और बस्तर—से लगभग 37 बटुक शामिल होंगे। कार्यक्रम को सुव्यवस्थित बनाने के लिए आयोजन समिति की बैठक आयोजित कर विभिन्न जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु शशिकांत मिश्रा को संयोजक बनाया गया है, जबकि सह-संयोजक के रूप में प्रमोद कुमार मिश्रा और अनुराग पांडेय सहित अन्य सदस्य जिम्मेदारी निभाएंगे। आयोजन में समाज के पदाधिकारी, संरक्षकगण, महिलाएं और बटुकों के अभिभावक भी बड़ी संख्या में शामिल रहेंगे। यह सामूहिक संस्कार सामाजिक एकता और परंपराओं के संरक्षण का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।

बैठक में अध्यक्ष सुरेश मिश्रा, सचिव राज कुमार दीक्षित संरक्षक द्वय गिरजा शंकर दीक्षित, राज कुमार अवस्थी, शशिकांत मिश्रा संयोजक उपनयन समिति, सह-संयोजक - प्रमोद कुमार मिश्रा, अनुराग पाण्डेय, प्रकाश अवस्थी, अशोक दीक्षित, आशीष बाजपेयी, लखन लाल बाजपेयी, श्रीमती गीता मिश्रा, श्रीमती अचर्ना मिश्रा, श्रीमती अंजू पाण्डेय, श्रीमती स्वाति अवस्थी, श्रीमती रंजू त्रिवेदी, श्रीमती ममता त्रिवेदी, सत्यदेव तिवारी, राजेश त्रिवेदी, प्रभात मिश्रा (जूनियर) सहित बटुकों के अभिभावक उपस्थित रहें।

खेल सुविधाओं का विस्तार युवाओं को नई दिशा और अवसर देता है- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने जशपुर में मल्टीपरपज इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम का किया शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर में 3 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से निर्मित मल्टीपरपज इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खेल अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने के बेहतर अवसर प्रदान करता है और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्टेडियम का अवलोकन किया और वहां उपस्थित खिलाड़ियों के साथ खेल का आनंद भी लिया। उन्होंने खिलाड़ियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि सरकार प्रदेश में खेल सुविधाओं के

विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी उचित मंच मिल सके। उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, टीमवर्क और आत्मविश्वास विकसित करने का सशक्त साधन है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर दिया जाए।

मल्टीपरपज इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम में खिलाड़ियों को बास्केटबॉल के साथ-साथ शतरंज, कैरम और टेबल टेनिस जैसे खेलों का अभ्यास करने की आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी। यह स्टेडियम न केवल खेल गतिविधियों को बढ़ावा देगा, बल्कि जशपुर क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बनेगा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कमर्कार कल्याण मंडल के अध्यक्ष रामप्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविन्द भगत, कृष्णा राय, नगर पालिका उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जुदेव, जिला पंचायत अध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जुदेव, जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगाराम भगत, विजय आदित्य सिंह जुदेव, सरगुजा कमिश्नर नरेन्द्र दुग्गा, आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह, डीएफओ शशि कुमार, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार, खिलाड़ी और कोच उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने इचकेला की बालिका क्रिकेट खिलाड़ियों को किया सम्मानित : क्रिकेट किट प्रदान कर बढ़ाया उत्साह

मुख्यमंत्री साय ने मल्टीपरपज इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम में ग्राम इचकेला की छत्तीसगढ़ बालिका क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें क्रिकेट किट प्रदान करते हुए सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इन प्रतिभाशाली बालिकाओं ने अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन से न केवल जिले, बल्कि पूरे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। उन्होंने छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अनुशासन, समर्पण और निरंतर अभ्यास के बल पर वे भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करेंगी तथा देश का नाम रोशन करेंगी।

उल्लेखनीय है कि जशपुर के इचकेला स्थित शासकीय प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास की बालिकाएँ क्रिकेट के क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही हैं। वतर्मान में इस समूह की 17 बालिकाएँ अंडर-17 एवं अंडर-19 वर्ग में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जबकि लगभग 40 खिलाड़ी नियमित रूप से क्रिकेट का अभ्यास कर रही हैं। वर्ष 2025 में सरगुजा संभाग ने 25 वर्षों के अंतराल के बाद अंडर-17 राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा, जिसमें विजेता टीम के 11 में से 9 खिलाड़ी इचकेला एमसीसी से थीं। इसी प्रकार अंडर-19 वर्ग में सरगुजा संभाग ने रजत पदक अर्जित किया, जिसमें 11 में से 8 खिलाड़ी इचकेला एमसीसी से शामिल थीं। इसके अतिरिक्त रायगढ़ में आयोजित इंटर-स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 में भी इचकेला एमसीसी की बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए

प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब तक इस समूह की 11 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जिले और राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इन उपलब्धियों के लिए खिलाड़ियों के साथ-साथ उनके प्रशिक्षकों संतोष शंकर सोनी और श्रीमती पंडरी बाई के समर्पण और मार्गदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाना एक प्रेरणादायक उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्रामीण क्षेत्रों से निकल रही ऐसी प्रतिभाओं को हर संभव प्रोत्साहन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि छत्तीसगढ़ खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सके।

एक्साइज ड्यूटी की कमी से जनता को फायदा नहीं-दीपक बैज

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र सरकार ने डीजल को विशेष एक्साइज से मुक्त कर दिया है तथा पेट्रोल पर 10 रुपये की छूट किया है। एक्साइज ड्यूटी कम करने से जनता को कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ पेट्रोलियम कंपनियों का कवर होगा। यदि छूट दी गयी है तो डीजल, पेट्रोल के दाम जनता को सस्ता मिलना चाहिए। मोदी सरकार ने कोरोना काल में डीजल, पेट्रोल पर एक्साइज बेतहाशा बढ़ाया था, जिससे केंद्र ने जनता से 45000 करोड़ का मुनाफा कमाया था। अब युद्ध काल में उसी मुनाफे से जनता को राहत दी जाए। भाजपाई कल से बयान देकर भ्रम फैला रहे।

आबकारी मेन्स पावर सप्लाई घोटाले की जांच ईडी, ईओडब्ल्यू कब जांच करेगी : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आबकारी विभाग में मेन्स पावर सप्लाई का काम भाजपा के एक राष्ट्रीय नेता की कंपनी को गलत तरीके से दिया गया है। 300 करोड़ के इस घोटाले की जांच ईडी, ईओडब्ल्यू कब करेगी? प्रदेश की जनता जानना चाहती है, गुजरात के किस नेता के इशारे पर यह घोटाला किया गया। मुख्यमंत्री, आबकारी मंत्री इस घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेंगे?

अफीम के बाद गांजे की खेती का खुलासा : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में 6 जगह अफीम की खेती के खुलासे के बाद अब कोंडागांव के केशकाल ब्लॉक में गांजे की खेती का खुलासा हुआ है। मक्के की खेती के बीच गांजे की खेती हो रही थी। तीन दिन पहले सरकार ने 30 जिला कलेक्टरों के हवाले से दावा किया कि कलेक्टरों ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाकर तफ्तीश किया कहीं पर अफीम, गांजे आदि की खेती नहीं हो रही है। केशकाल में गांजे की खेती के खुलासे से साफ हो गया कि कलेक्टरों ने सरकार को गलत रिपोर्ट दी या सरकार ने कलेक्टरों के माध्यम से जनता से झूठ बोला। सरकार बताये कि अब वह कलेक्टर पर कार्यवाही करेगी।

सरकार की वित्तीय स्थिति बदहाल, ठेकेदार आत्महत्या की धमकी दे रहे : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश सरकार की वित्तीय हालात गंभीर हो चुकी है। खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण सरकार ने निर्माण कार्य, विकास कार्य बंद कर दिया है। अब तो सरकार छोटे-छोटे पेमेंट भी ठेकेदारों का नहीं कर पा रही है। पीएचई के एक ठेकेदार ने अपना काम पूरा कर लिया, सरकार उसका पेमेंट नहीं दे पा रही, उसने 30 मार्च पीएचई ऑफिस के सामने आत्मदाह की धमकी दिया है।

धान खरीदी बंद हुए 2 माह होने जा रहा, धान संग्रहण केंद्रों पर पड़ा है : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी को बंद हुए 2 माह पूरा होने जा रहा, सरकार अभी संग्रहण केंद्रों से धान का उठाव नहीं करवा पा रही है। मिलर धान लेने आवेदन कर रहे, अनुबंध भी कर चुके है, सरकार मिलरों को डीओ नहीं दे रही। धान सूख रहा, बेमौसम बारिश से भीग भी रहा, खराब हो रहा। सरकार भ्रष्टाचार करने की नीयत से धान का उठाव नहीं करवा रही, ताकि खराब होने का बहाना बना कर भ्रष्टाचार किया जा सके। एक बार फिर से चूहों को बदनाम करने की तैयारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री करेंगे कुंवरगढ़ महोत्सव का शुभारंभ

133 करोड़ की विकास परियोजनाओं की मिलेगी सौगात

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

धरसीवां में आयोजित प्रेस वार्ता में स्थानीय विधायक अनुज शर्मा ने जानकारी दी कि आगामी 31 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह्यकुंवरगढ़ महोत्सवव्ह का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर क्षेत्र को 133 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिलेगी। विधायक शर्मा ने बताया कि यह महोत्सव क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के साथ-साथ स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि कुंरा नगर अपनी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है, जहां राजा कुँवर सिंह गोंड की विरासत आज भी जीवंत है।

उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया जाएगा, साथ ही क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए नव निर्मित तहसील कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में आधारभूत संरचना, सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।

महोत्सव के दौरान स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन एवं कुटीर उद्योगों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे स्थानीय व्यापारियों एवं कारीगरों को आर्थिक लाभ मिलेगा। साथ ही कार्यक्रम में स्थानीय लोक कलाकारों के साथ राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों की प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

विधायक शर्मा ने क्षेत्रवासियों से इस ऐतिहासिक आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के लिए सुरक्षा एवं पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि आगंतुकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि कुंवरगढ़ महोत्सव क्षेत्र के इतिहास में पहली बार आयोजित हो रहा है, जो सांस्कृतिक गौरव एवं विकास के नए अध्याय की शुरुआत करेगा।

प्रेस वार्ता में जनपद पंचायत अध्यक्ष सुश्री शकुंतला सेन, उपाध्यक्ष दिनेश खुटे, नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद साहू, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, एसडीएम नंदकुमार चौबे, सहित जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

छग डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, नई समिति का गठन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह एवं जिला प्रशासन रायपुर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के चुनाव शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हुए। यह चुनाव कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही।

मसीही समाज के प्रतिनिधियों ने चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन के सहयोग से लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान संभव हो सका है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर, एसडीएम श्रीमती तुलसी राठौर, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता एवं पारदशिर्ता के साथ सम्पन्न कराई गई।

चुनाव उपरांत नई प्रबंधन समिति का गठन किया गया जिसमें द राइट रेव्ह सुषमा कुमार को पदेन चेयरमैन, नितिन लॉरेंस को उपाध्यक्ष, जयदीप रॉबिन्सन को सचिव एवं प्रवीण मसीह को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया एवं अमित दास, रेव्ह समीर फ्रैंकलिन, श्रीमती तनुजा पॉल को सदस्य मनोनीत किया गया। नवगठित समिति ने संस्था के सुचारू संचालन एवं शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। समिति ने स्पष्ट किया कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा आर्थिक अनियमितताओं एवं फर्जी दस्तावेजों के मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा संस्था की छवि को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रशासन के सहयोग से शीघ्र ही स्थिति पूर्णतः सामान्य हो जाएगी।

संपादकीय

तारीफ तब ही होती है जब आदमी सफल होता है

विश्व राजनीति हो या देश की अंदरूनी राजनीति हो,किसी नेता की तब ही तारीफ की जाती है जब जो काम हाथ में लेता है, उसे पूरा करके दिखाता है ।जो लक्ष्य तय किया उसे हासिल करके दिखाता है। जो कहा उसे करके दिखाता है। ऐसे नेता पर विश्व भी भरोसा करता है और देश भी भरोसा करता है। ऐसे नेता से ही यह उम्मीद की जाती है कि जो काम कोई और नेता नहीं कर पा रहा है, उसे यह नेता कर सकता है। उसके बारे में एक के बाद एक नेता कहते रहते हैं, उम्मीद जताते रहते हैं कि इस नेता को आगे आकर यह काम करना चाहिए। विश्व में इस समय ईरान,इजराइल व अमरीका के युध्द के कारण संकट में है। ऊर्जा सप्लाई बाधित होने से सभी देश कम ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में विश्व के कई लोग कह चुके हैं कि पीएम मोदी ही यह युध्द रुकवा सकते हैं। उनको आगे आकर यह युध्द रुकवाने का प्रयास करना चाहिए।

जब दुनिया के कई देश के नेता यह कहते हैं कि युध्द पीएम ही रुकवा सकते हैं तो यह देश के लोगों के लिए जहां गौरव की बात होती है वहीं कांग्रेस यह सुनकर जलभुन जाती है क्योंकि वह आज तक पीएम मोदी को असफल नेता मानती आई है और वह आए दिन हर मसले पर बयान देती रहती है कि पीएम मोदी इस मामले असफल है। पीएम मोदी विदेश नीति मामले में असफल हैं। वह अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान पर तो यकीन करती है कि भारत पाक युध्द मैंने रुकवा दिया और पीएम मोदी पर आरोप लगाती है कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन वही ट्रंप जब यह कहते हैं कि विश्व में पीएम मोदी और मैं ही ऐसे दो नेता हैं जो काम हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। यह बात विश्व के और किसी नेता के बार में नहीं कही जा सकती। इस पर कांग्रेस यकीन नही करेगी, नहीं कहेगी की ट्रंप सच कह रहे हैं।

कांग्रेस को ट्रंप तब सच कहते हुए लगते हैं जब उनके बयान के आधार पर पीएम मोदी को नीचा दिखाया जा सकता है,असफल बताया जा सकता हो ।कांग्रेस तो ऐसे मौके की तलाश में रहती है जब वह पीएम को असफल बता सके। कंप्रोमाइस्ड नेता बता सके। हाल ही में कांग्रेस को ऐसा मौका फिर मिला जब अमरीका ने पाकिस्तान को ईरान से शांति वार्ता के लिए मैसेंजर की भूमिका सौंपी तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि प. एशिया में शांति बहाली के लिए आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान का नाम सामने आना भारत की कूटनीतिक विफलता है। इससे पाकिस्तान विश्व मंच पर प्रासंगिक बनता जा रहा है। मोदी सरकार की कूटनीति,वैश्विक संपर्क और नैरेटिव प्रबंधन की कमजोरियों के कारण एक अस्थिर देश को पाकिस्तान को ब्रोकर की भूमिका मिल गई है। इससे भारत की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

कांग्रेस भूल सकती है कि पाकिस्तान तो कठपुतली है, उससे जो कहा जाता है वह करता है। अभी अमरीका ने उससे कहा कि शांति की संदेश ईरान को देना है तो वह देने को तैयार हो गया। उसकी कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है इसलिए वह इंकार नहीं कर सकता ।उसकी कोई हैसियत विश्व में नहीं है, इसलिए ईरान ने ही साफ कह दिया कि उसे पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। कहां कांग्रेस मान रही थी कि विश्व में पाकिस्तान को महत्व मिल रहा है, कहां ईरान ने बात करने से ही मना कर दिया। इससे कांग्रेस की सोच पर देश के लोगों को हंसी आती है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी मोदी से नफरत से चलते देश को भी कई बार नीचा दिखाने से बाज नही आती है। वह पीएम मोदी को असफल बताने के लिए देश को असफल बताने लगती है।

इस नफरत के कारण वह समझ नहीं पाती है कि पाकिस्तान शांति के लिए मध्यस्थ हो ही नहीं सकता। वह डाकिया हो सकता है। पाकिस्तान और भारत की कोई तुलना नहीं हो सकती। पाकिस्तान की कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है,जबकि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है। यही वजह है कि भारत अमरीका की कोई भी बात मानने से मना कर सकता है और फिर भी अमरीका भारत के पीएम की तारीफ कर सकता है। यह तारीफ इसीलिए होती है कि पीएम मोदी शांति व संवाद पर यकीन रखने वाले नेता हैं और वह दुनिया में शांति के लिए कई देशों से संवाद करते रहते है। वह हर देश से बात करने की क्षमता रखते हैं। हर देश उनकी बात सुनता भी है और मानता भी है क्योंकि वह विश्व के हित में बात करते है। जब युध्दरत देश शांति चाहेंगे तो ही मोदी पीसमेकर की भूमिका निबाहने सामने आएंगे। कांग्रेस चाहती है कि वह पाकिस्तान के पीएम की तरह भूमिका निबाहें तो यह कांग्रेस की सोच है, पीएम मोदी की सोच कांग्रेस की सोच से बेहतर है। कांग्रेस उनके समान सोच नहीं सकती।

		3					7	
9				6		3		8
	7		9		5		6	
						1		9
3		8		7			5	
	1		3		9			7
		2		8		7		
	8				2		4	3
			1					

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.355 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

हौसला, हुनर और योजनाओं के सहारे महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले का छोटा सा गांव मनियारी आज एक बड़ी सीख दे रहा है- अगर इरादे मजबूत हों और सही मौके मिल जाएं, तो बदलाव दूर नहीं होता। यहां की पांच महिलाओं ने अपने साहस, आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव में नई सोच की शुरुआत कर दी।

इस बदलाव की शुरुआत हुई अनुसूया साहू से। बचपन से सिलाई में माहिर अनुसूया के पास हुनर तो था, लेकिन आर्थिक तंगी और संसाधनों की कमी के चलते वह आगे नहीं बढ़ पा रही थीं। घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उनका सपना कहीं दब सा गया था। मार्च 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को 1000 हजार रूपए की प्रत्येक माह आर्थिक मदद दिए जाने के उद्देश्य से शुरू की गई महतारी वंदन योजना ने उनके जीवन में नई उम्मीद जगाई। हर महीने मिलने वाली इस सहायता राशि को खर्च करने के बजाय उन्होंने बचाने का फैसला किया। छह महीने की बचत के बाद उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी और घर से ही काम शुरू किया। शुरुआत भले ही छोटी थी, कपड़ों की आल्टरिंग और साधारण सिलाई, लेकिन काम की गुणवत्ता ने जल्द ही उन्हें पहचान दिला दी।

अनुसूया की कोशिशों ने गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। ओमकारेश्वरी साहू ने उनसे सिलाई सीखी और अपना काम शुरू किया। इसके बाद पावर्ती, गंगा और हेमिनी भी जुड़ती चली गईं। देखते ही देखते यह पहल एक मजबूत महिला समूह में बदल गई, जहां सहयोग और सीखने की भावना ने इसे आगे बढ़ाया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इन महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की जानकारी दी और पंजीकरण में मदद की। योजना के तहत मिली 5000 रुपये की सहायता राशि का उपयोग महिलाओं ने सिलाई मशीन खरीदने और अपने काम को विस्तार देने में किया। सही जानकारी और योजनाओं के उपयोग ने इनके आत्मविश्वास को नई उड़ान दी। आज ये पांचों महिलाएं मिलकर एक सफल सिलाई केंद्र चला रही हैं। वे महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए कपड़े तैयार कर रही हैं। समय पर काम और बेहतर गुणवत्ता के कारण गांव के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में भी उनकी पहचान बन चुकी है।

इस पहल से उनकी आय में वृद्धि हुई है। अब वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दे रही हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब वे परिवार के फैसलों में भी बराबरी से भागीदारी निभा रही हैं। इन महिलाओं की सफलता अब गांव की अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ वे समाज में नई पहचान बना रही हैं।

पीएम जनमन योजना से बदल रही विशेष पिछड़ी जनजातियों की तस्वीर

नई दृष्टिबिंदु / अंबिकापुर

राज्य में संचालित प्रधानमंत्री जनमन योजना विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। इस योजना के माध्यम से दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले पात्र हितग्राहियों को आवास सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मलंगवा खुर्द की निवासी भेन्दकी के जीवन में भी इस योजना ने नई उम्मीद जगाई है। वर्षों तक कच्चे और जर्जर मकान में रहने के बाद अब उन्हें पक्का आवास उपलब्ध हुआ है, जिससे उन्हें सुरक्षित जीवन का आधार मिला है। पूर्व में कच्चे मकान में रहने के कारण विशेषकर बारिश के मौसम में छत से पानी टपकने और दीवार गिरने का भय बना रहता था। अब पक्का घर मिलने से इन समस्याओं

से राहत मिली है और उनका जीवन अधिक सुरक्षित हो गया है।

अकेले जीवन यापन कर रहीं भेन्दकी के लिए यह आवास केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया है। उन्होंने बताया कि अब उन्हें किसी प्रकार की असुरक्षा का भय नहीं है और जीवन पहले की तुलना में अधिक सहज हो गया है ।योजना से लाभान्वित हितग्राहियों ने इस सुविधा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

प्रधानमंत्री जनमन योजना का उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवास, स्वास्थ्य, बिजली और स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राज्य में इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से हजारों हितग्राहियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।

पीएम मत्स्य संपदा योजना : मछली पालन और कृषि से किसान पाकलू हुए सशक्त

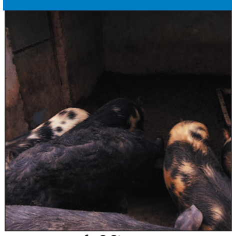

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना छत्तीसगढ़ के मत्स्य किसानों को सशक्त बनाने में सार्थक कदम बन रही है। इसी क्रम में कोंडागांव जिले के मत्स्य पालन विभाग सहित राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों की आजीविका को सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर जिले के ग्राम पल्ली निवासी युवा किसान श्री पाकलू मरकाम ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नई मिसाल कायम की है।

श्री मरकाम ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अपनी भूमि में तालाब निर्माण कर मछली पालन की शुरुआत की। आज वे न केवल मछली पालन कर रहे हैं, बल्कि समन्वित कृषि प्रणाली अपनाकर सालाना लगभग 6 लाख रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में उन्हें इस योजना के तहत तालाब निर्माण के लिए 11 लाख रुपये की लागत पर 6 लाख 60 हजार रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ।

वर्तमान में उनके पास 3 तालाब हैं, जिनमें वे रोहू, कतला, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और पंगास जैसी विभिन्न प्रजातियों की मछलियों का पालन कर रहे हैं। मछली पालन के साथ-साथ उन्होंने मुर्गी पालन, सूकर पालन तथा कृषि को भी अपनाया है। मुर्गी पालन में वे सोनाली, एवं देसी नस्ल की मुगिर्यों का पालन कर रहे हैं। वहीं मुर्गा लड़ाई के लिए प्रसिद्ध असील प्रजाति के मुर्गे का

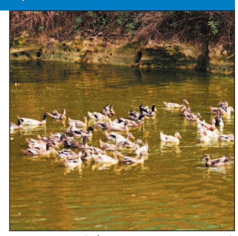

भी पालन कर रहे है जिसकी कीमत सामान्य मुर्गे से कई गुना अधिक होती है। इसके अतिरिक्त उनके पास लगभग 20 नग सूकर हैं तथा खाकी कैंपबेल, इंडियन रनर और मोती प्रजाति के बत्तख भी हैं, जो उनकी आय का अतिरिक्त स्रोत हैं। साथ ही वे मक्के सहित अन्य फसलों की खेती भी कर रहे हैं। समन्वित कृषि प्रणाली के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों को जोड़कर श्री मरकाम ने अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आज वे न केवल आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत भी हैं।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन : किसान प्रमोद खेती से बना आत्मनिर्भर

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्य सरकार प्रदेश में किसानों के आय को बढ़ाने के लिए उद्यानिकी की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले के विकासखण्ड बागबाहरा अंतर्गत ग्राम करमापटपर (भदरसी) के किसान प्रमोद चंद्राकर ने सीमित भूमि संसाधनों के बावजूद राष्ट्रीय बागवानी मिशन के सहयोग, नवाचार और आधुनिक तकनीक व अपनी मेहनत से उद्यानिकी खेती में सफलता प्राप्त की है। वे उद्यानिकी फसलों के जरिए आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ रहे है।

किसान श्री चंद्राकर बताते है कि उनके पास कुल 0.41 हेक्टेयर भूमि है, जो पहले पारंपरिक रूप से धान की खेती के लिए उपयोग में लाई जाती थी। इस पद्धति में लागत अधिक और उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता था। लेकिन समय के साथ उन्होंने खेती में बदलाव लाने का निर्णय लिया और उद्यानिकी फसलों की ओर कदम बढ़ाया।

उन्होंने ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीक को अपनाया, जिससे पानी की बचत के साथ-साथ फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अब वे खरीफ और रबी दोनों सीजन में धनिया, प्याज और गेंदा फसलों की खेती कर रहे हैं। श्री प्रमोद चंद्राकर बताते हैं कि उन्होंने धनिया की खेती से प्रति एकड़ लगभग 5 से 6 क्विंटल उत्पादन प्राप्त किया। इस उत्पादन से उन्हें प्रति एकड़ लगभग 50 हजार रुपये तक का मुनाफा हुआ। यह लाभ उन्हें इनपुट लागत, श्रमिक खर्च और अन्य सभी व्ययों को निकालने के बाद प्राप्त हुआ है। श्री प्रमोद चंद्राकर की इस उपलब्धि से पूरे गांव के लोग प्रेरित हुए हैं। उनके मार्गदर्शन और अनुभव से प्रभावित होकर अन्य किसान भी अब उद्यानिकी फसलों की खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

रायपुर : ग्राम गिधली बसना हर घर जल ग्राम के रूप में प्रमाणित, घर में पेयजल की सुविधा से समय का हो रहा बचत: रेखा भोई

जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार प्रदेश के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहूंचाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। यह योजना महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के ग्राम गिधली में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना ने ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली लाई है।

ग्रामीण बताते हैं कि गांव के लोगों की सुबह की दिनचर्या पानी की समस्या से शुरू होती थी। ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए हैंडपंप और पावर पंप पर निर्भर रहना पड़ता था। गर्मी के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती थी, जब पानी के स्रोत सूखने लगते थे और लोगों को दूर-दूर तक पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। इससे समय और श्रम दोनों की बर्बादी होती थी, महिलाओं को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

परिस्थिति में बदलाव तब आया जब जल जीवन मिशन के तहत गांव में कार्य प्रारंभ हुआ। इस योजना के अंतर्गत लगभग 100 .52 लाख रुपये की लागत से एक पानी टंकी का निर्माण किया गया और करीब 4644 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई। जिससे गांव के 250 घरों में नल कनेक्शन प्रदान किए गए। पहले जहां गांव में 9 हैंडपंप और 5 पावर पंप ही जल का मुख्य स्रोत थे, वहीं अब सभी घरों तक सीधे स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। इस सफलता में ग्राम पंचायत के सरपंच शोभित मांझी का नेतृत्व और ग्रामीणों का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा। इसी का परिणाम है कि 17 अप्रैल 2025 को ग्राम गिधली को हर घर जल ग्राम के रूप में प्रमाणित किया गया। गांव की लाभार्थी श्रीमती रेखा भोई बताती हैं कि पहले उन्हें पानी भरने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और मेहनत दोनों अधिक लगते थे। लेकिन अब घर में नल कनेक्शन मिलने से उन्हें आसानी से स्वच्छ पानी उपलब्ध हो जाता है। इससे उनका समय बचता है, जिसे वे अब घर और अन्य उपयोगी कार्यों में लगा पाती हैं, जिससे समय सदुपयोग हो रहा है।

भारत में वैश्विक शिक्षा : बढ़ने लगी है विदेशी छात्रों की तादाद

हरिशंकर व्यास

वर्ष 2030 तक भारत आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में हर साल लगभग आठ प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी का अनुमान है। जहां वर्ष 2022 में 39 हजार से अधिक विदेशी छात्र भारत आए थे, वहीं वर्तमान में लगभग 200 देशों के 72 हजार से अधिक विदेशी छात्र भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत हैं।

हाल ही में 25 मार्च को वैश्विक उच्च शिक्षा सेवाओं का मूल्यांकन करने वाली अग्रणी कंपनी ब्रिटेन स्थित क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंड्स द्वारा प्रकाशित 16वीं वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 2025 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। भारत ने इस साल विभिन्न विषयों और संकाय क्षेत्रों में शीर्ष 50 में से 27 स्थान हासिल किए हैं, जो कि पिछले वर्ष 2024 में दर्ज किए गए 12 स्थानों की तुलना में दोगुने से भी अधिक हैं। कह सकते हैं कि यह रैंकिंग भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की बढ़ती वैश्विक साख और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाती है।

रिपोर्ट के अनुसार भारत एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा गंतव्य देश बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही वर्ष 2030 तक भारत आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में हर साल लगभग आठ प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी का अनुमान है। जहां वर्ष 2022 में 39 हजार से अधिक विदेशी छात्र भारत आए थे, वहीं वर्तमान में लगभग 200 देशों के 72 हजार से अधिक विदेशी छात्र भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत हैं। अब केंद्र सरकार ने ह्यस्टडी इन इंडियाह्ल पहल के तहत 2030 तक प्रतिवर्ष 2 लाख विदेशी छात्रों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। निःसंदेह, भारत वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित होने की राह पर आगे बढ़ रहा है। अब हर साल बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण कौशल, अनुसंधान सुविधाओं और उच्च शिक्षा के बाद विदेश में ही करिअर के अवसरों को पाने के मद्देनजर विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या लगातार घट रही है।

भारत में विदेशी छात्रों की संख्या बढ़ने की कई वजहें हैं। सरकार ने पिछले कुछ सालों में ह्यनेशनल एजुकेशन पॉलिसीह्ल (एनईपी) 2020 के जरिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए गए हैं। एनईपी के तहत एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने, मान्यता देने की व्यवस्था मजबूत करने, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल एजुकेशन का विस्तार करने का अभियान लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे गुणात्मक सुधार से भारत के शिक्षा संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मान्यता मिल रही है।

वैश्विक स्तर की शिक्षा व्यवस्था को भारत में लाने के मद्देनजर 19 विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस स्थापित करने की इजाजत दी गई है। इससे जिस वैश्विक शिक्षा के लिए पहले छात्रों को विदेश जाना पड़ता था, अब वही शिक्षा आसानी से भारत में ही मिलने की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। निश्चित रूप से विदेशी यूनिवर्सिटीज को भी भारत में बड़ी संख्या में छात्र मिलने का लाभ है। भारत में उच्च शिक्षा की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। चूंकि वैश्विक यूनिवर्सिटीज भारत में डिग्री प्रदान कर सकती हैं, अतएव छात्रों के लिए विदेश जाने के खर्च और अनिश्चितताओं के बिना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भारत में ही लेना लाभप्रद है। इतना ही नहीं, भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा के प्रमुख गंतव्य देश, खासकर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में आव्रजन नियमों में सख्ती आई है और वीजा जांच के अलावा वित्तीय लागत बढ़ गई है।

हाल ही में प्रकाशित अमेरिका के स्टेट डिपाटर्मेंट की रिपोर्ट मार्च 2026 के मुताबिक पिछले वर्ष जनवरी से अगस्त 2025 के बीच अमेरिका द्वारा परमानेंट रेजिडेंट और टेंपरेरी वीजा मंजूरी में साल भर पहले की तुलना में 11 फीसदी की कमी आई है। इतना ही नहीं अमेरिका में जो छात्र अध्ययनरत हैं, उनके लिए भी रोजगार ढूंढ़ना मुश्किल हो गया है।

सरकार हरसंभव तरीके से भारत को वैश्विक शिक्षा व डिजिटल शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए प्रयास कर रही है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के तहत शिक्षा व्यवस्था के विभिन्न आवंटनों को वैश्विक शिक्षा और अर्थव्यवस्था की वास्तविक जरूरतों के मद्देनजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इनोवेशन, ऑटोमेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल बिजनेस से सम्बद्ध करने संबंधी प्रभावी पहल की गई है।

भारत के पास बदलते हुए दौर में उच्च शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनने के अवसर मौजूद हैं। देश को शिक्षा के तहत आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में तेजी से उन्नत कौशल विकसित करने की रणनीति अपनाना होगी। देश में वैश्विक शिक्षा को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण बनाकर खासतौर से एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया सहित कई विकसित और विकासशील देशों के छात्रों के कदम भारत की यूनिवर्सिटीज की ओर मोड़ने के लिए प्रयास करने होंगे। भारत को इंजीनियरिंग, प्रबंधन, स्वास्थ्य विज्ञान, डिजाइन, मीडिया और उभरती प्रौद्योगिकियों की वैश्विक शिक्षा का हब बनाने के विशेष प्रयत्न करने होंगे। देश की यूनिवर्सिटीज को उद्यमिता, नवाचार, अनुसंधान की गुणवत्ता, प्रयोगशालाओं में निरंतर निवेश, वैश्विक संस्थानों के साथ आसान सहयोग, नियामक ढांचों के लिए कठोर मानकों के साथ यूनिवर्सिटिज को अधिक स्वायत्तता से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना होगा।

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन कर पात्र हितग्राहियों को करें लाभान्वित- संभाग आयुक्त राठौर

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में जिले के विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागों द्वारा संचालित कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर तुलिका प्रजापति, डीएफओ दिनेश पटेल, सीईओ जिला पंचायत भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर जीआर मरकाम, अपर कलेक्टर मिथलेश डोंडे, एसडीएम मानपुर अमित नाथ योगी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

श्री राठौर ने कहा कि जिले का समग्र विकास एवं आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। अतः कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों तथा पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की गई। उन्होंने एसडीएम को निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों

की भी समीक्षा की। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण एवं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

खाद्य विभाग के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण, भंडारण एवं बायोमैट्रिक व्यवस्था की गहन समीक्षा की। उद्योग विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने औद्योगिक योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए जिले में राइस मिल संचालन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उन्नत फसलों की स्थिति की जानकारी ली गई। उन्होंने मक्का प्रोसेसिंग यूनिट हेतु औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, एग्रो आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने एवं फसल परिवर्तन अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में कुपोषण दर तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की प्रगति पर चर्चा की। स्वास्थ्य विभाग से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर तथा संस्थागत प्रसव की स्थिति की जानकारी लेकर आवश्यक सुधार हेतु निर्देश दिए। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति एवं एकल शिक्षक वाले स्कूलों में पंचायत स्तर पर शिक्षक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। पशुपालन विभाग, आयुष विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा निर्माण कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

खास खबर

कलेक्टर ने अवर्धा जलाशय और बोटेपार जलाशय का किया निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने अवर्धा जलाशय एवं बोटेपार जलाशय से निकलने वाली निर्माणाधीन पक्की नहर लाईनिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने नहर लाइनिंग की कुल लंबाई, निर्माण गुणवत्ता, कार्य की गति तथा डेम की उपलब्ध क्षमता संबंधी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिससे आगामी सीजन में किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके।

उन्होंने कहा कि पक्की नहर लाइनिंग कार्य से किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई का स्थायी लाभ मिलेगा। कलेक्टर ने नहर किनारे उपस्थित किसानों से सीधे संवाद कर नहर लाइनिंग कार्य से मिलने वाले लाभ और गांव की समस्याओं की जानकारी ली। किसानों ने बताया कि पक्की नहर लाइनिंग बनने से पानी का रिसाव कम होगा, सिंचाई सुचारू रूप से खेतों तक पहुंचेगी तथा उत्पादन में वृद्धि की संभावना बढ़ेगी।

कलेक्टर ने किसानों को पीएम आशा योजना के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत दलहन एवं तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है, जिससे किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी। उन्होंने किसानों को दलहन-तिलहन क्षेत्र विस्तार के लिए प्रेरित किया तथा समय पर पंजीयन कराने कहा। इस अवसर पर ग्राम बोटेपार के किसानों ने सीसी रोड एवं नाली निर्माण की मांग रखी। कलेक्टर ने उनकी मांगों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को सीसी रोड एवं नाली निर्माण का स्टीमेट तैयार कर बारिश के पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि गांव में आवागमन एवं जल निकासी की समस्याओं का समाधान हो सके। कलेक्टर ने किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सिंचाई संबंधी सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ तथा पारदर्शिता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिससे रबी एवं खरीफ सीजन के लिए किसानों को पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता एनके रामटेके, एसडीओ सुयश यदु, उप अभियंता सहित किसान उपस्थित थे।

स्वदेशी अपनाने से मजबूत होगी देश की अर्थव्यवस्था-शर्मा

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कवर्धा में किया स्वदेशी मेला का उद्घाटन

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने कवर्धा के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित भव्य स्वदेशी मेला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी मेला स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने स्वदेशी मेला में लगे प्रदशर्नी एवं विक्रय स्टॉलों का अवलोकन किया।

इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण कर स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली और उनके निर्माण एवं विशेषताओं के बारे में विस्तार से जाना। 27 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित इस मेले में स्वदेशी वस्तुओं के कई स्टॉल लगाए गए हैं, जहां स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया जा रहा है। भारतीय विपणन विकास केंद्र स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की इकाई द्वारा आयोजित यह मेला स्थानीय प्रतिभाओं और स्वदेशी उत्पादों को मंच प्रदान कर रहा है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मेले में लगे सभी स्टॉल भारत में निर्मित उत्पादों के हैं, जो स्वदेशी भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी जनसंख्या के अनुसार हमारा बाजार भी बहुत बड़ा है और यदि हम अपने ही बाजार का सही उपयोग करें, तो अपनी आर्थिक स्थिति के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्य केवल सरकार के माध्यम से नहीं, बल्कि समाज के माध्यम से संभव है। समाज एक बहुत बड़ी ताकत है और यदि समाज के लोगों में स्वदेशी अपनाने का भाव जागृत हो जाए, तो बड़े परिवर्तन संभव हैं। उपमुख्यमंत्री ने जापान जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के लोग अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसी प्रकार हमें भी स्वदेशी को अपनाते हुए देश में निर्मित उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि स्वदेशी का अर्थ है कि किसी भी उत्पाद में भारत के नागरिक का श्रम और पसीना शामिल हो। ऐसे आयोजनों से स्वदेशी के प्रति जागरूकता बढ़ती है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक डॉ. सियाराम साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नितेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, नगर पालिका

अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, पुलिस प्राधिकरण जवाबदेही के सदस्य भगत पटेल, जिला पंचायत सभापति राम कुमार भट्ट, जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विदेशी राम धुर्वे, मनीराम साहू, मेला प्रमुख मार्गदर्शक सुब्रत चाकी, संयोजक डॉ. अतुल जैन, सह संयोजक अमित बरडिया, संदीप अग्रवाल, शेखर बख्सी, राघव साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ऐश्वर्या पंडित ने बांधा समां

मेला के शुभारंभ अवसर पर बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ऐश्वर्या पंडित ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। उन्होंने हिंदी गीतों की मधुर प्रस्तुति से दशर्कों को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरे वातावरण को संगीतमय बना दिया। उल्लेखनीय है कि जिले में स्वदेशी मेला 27 मार्च से 2 अप्रैल तक संचालित किया जायेगा। मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है, इसमें विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिताएं उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान कर रही हैं। इस आयोजन के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उन्हें सीखने, आगे बढ़ने और आत्मविश्वास विकसित करने का बेहतर अवसर मिल रहा है।

भारत स्काउट्स व गाइड्स ने किया प्याऊ घर का शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा ठाकुर प्यारेलाल चौक में प्याऊ घर सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान प्याऊ घर सेवा के माध्यम से राहगीरों को शीतल पेय जल का वितरण स्काउट गाइड रोवर रेंजर द्वारा किया गया। यह प्याऊ घर सेवा त्रिशंख मंडल एवं हनुमान मंदिर समिति के सहयोग से आरंभ की गई है।

राजनांदगांव संभाग के डाकघरों में अंतर्राष्ट्रीय पार्सल सेवा

डाक विभाग द्वारा नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राजनांदगांव संभाग अंतर्गत आने वाले प्रधान डाकघर एवं उपडाकघरों में अंतर्राष्ट्रीय पार्सल, दस्तावेज एवं अन्य सामग्री की बुकिंग सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इस सुविधा के माध्यम से नागरिक अपने पार्सल, दस्तावेज एवं अन्य सामग्री को विश्व के विभिन्न देशों में सुरक्षित, सरल एवं व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से भेज सकते है। डाक विभाग की यह सेवा पूणर्त : सुरक्षित, पारदर्शी एवं विश्वसनीय है। पार्सल की सुरक्षित हैंडलिंग, उचित पैकेजिंग संबंधी मार्गदर्शन तथा समयबद्ध सेवा प्रदान की जाती है। साथ ही ऑनलाईन ट्रैकिंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इन डाकघरों में बुकिंग हेतु नागरिक अपना पार्सल, प्राप्तकर्ता का पूर्ण एवं सही पता तथा वैध पहचान पत्र प्रस्तुत कर एवं पार्सल का वजन एवं निर्धारित शुल्क जमा कर ट्रैकिंग रसीद प्राप्त कर सकते है। ट्रैकिंग रसीद के माध्यम से पार्सल की स्थिति ऑनलाईन देखी जा सकती है। डाक विभाग द्वारा बड़ा एवं भारी अंतर्राष्ट्रीय पासल के लिए डाकघर तक नि :शुल्क पिकअप की सुविधा प्रदान की जा रही है।

ईएसआईसी अस्पताल में श्रमिकों को मिल रही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा

नई दृष्टिबिंदु / रायगढ़

औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को बेहतर, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में ईएसआईसी अस्पताल रायगढ़ में सेवाओं का लगातार सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देशन पर जिला प्रशासन एवं कमर्चारी राज्य बीमा निगम के समन्वित प्रयासों से अब श्रमिकों को पहले की तुलना में अधिक प्रभावी एवं त्वरित उपचार सुविधा मिल रही है।

इसी क्रम में कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने कलेक्ट्रेट चेम्बर में अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सेवाओं के और विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया। उन्होंने अस्पताल को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित करते हुए श्रमिकों को अधिकतम स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पेयजल, विद्युत आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, चिकित्सक एवं स्टाफ सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने, निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा

परिवहन सुविधा को सुदृढ़ करते हुए बस सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया, ताकि श्रमिकों की पहुंच और अधिक सुगम हो सके। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

बता दे कि पतरापाली स्थित 100 बिस्तरों वाला यह अस्पताल बीमित श्रमिकों एवं उनके परिवारों के लिए एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। वतर्मान में अस्पताल में 15 चिकित्सक एवं आवश्यक तकनीकी स्टाफ कार्यरत हैं, जिससे उपचार व्यवस्था मजबूत हुई है। अस्पताल में शीघ्र ही भर्ती सुविधा प्रारंभ किए जाने की तैयारी है, जिससे गंभीर रोगों के उपचार के लिए श्रमिकों को अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अस्पताल परिसर में स्वच्छता एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन की बेहतर प्रणाली विकसित की जा रही है तथा मरीजों एवं चिकित्सकीय स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। अस्पताल में प्रयोगशाला सेवाएं प्रारंभ हो चुकी हैं तथा ऑपरेशन कक्ष सहित अन्य आवश्यक अवसंरचनात्मक कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जल निकासी व्यवस्था को भी बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि विभाग द्वारा जिले के सभी उद्योगों के लिए रोस्टर जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत क्रमानुसार कारखाना प्रबन्धन श्रमिकों को उत्तम स्वास्थ लाभ हेतु जाँच के लिए ईएसआईसी हॉस्पिटल ले कर आएगा। साथ ही बीमित श्रमिक स्वयं अपने परिवार के सदस्यों के साथ जाँच के लिए ईएसआईसी हॉस्पिटल जा सकते है। विभाग द्वारा श्रमिकों को योजना का लाभ लेने के लिए निरंतर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की योजना संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, आर्थिक सहायता, मातृत्व लाभ, दुर्घटना मुआवजा एवं पेंशन जैसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस योजना में कमर्चारी एवं नियोक्ता दोनों द्वारा अंशदान किया जाता है, जिससे श्रमिकों को व्यापक सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना से जिले के 2264 हितग्राही हुए लाभान्वित

नई दृष्टिबिंदु / मोहला

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत बलौदा बाजार के पंडित चक्रपाणि शुक्ल हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय राशि वितरण कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबाकर राज्य के 4 लाख 95 हजार 965 हितग्राहियों के खाते में 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपए हस्तांतरित किए।

रिमोट का बटन दबाते ही जिले के हितग्राहियों के खातों में 10 हजार रुपए की राशि अंतरित हुई। इनमें तहसील मोहला के 457, तहसील मानपुर के 681, तहसील चौकी के 748, तहसील खड़गांव के 164 एवं तहसील औंधी के 214 हितग्राही शामिल हैं। इस तरह जिले के कुल 2 हजार 264 हितग्राही लाभान्वित हुए। कार्यक्रम में सांकेतिक रूप से 10 हितग्राहियों को उनके खातों में राशि हस्तांतरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

जिला स्तरीय राशि वितरण कार्यक्रम जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह के मुख्य आतिथ्य में कलेक्ट्रेट कार्यालय सभा कक्ष में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर जी. आर. मरकाम, डिप्टी कलेक्टर डीआर ध्रुव सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित थे।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शासन दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। हमें इस सहयोग राशि का बेहतर उपयोग कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। समाज के समग्र विकास में हम सभी की भागीदारी आवश्यक है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का लाइव प्रसारण देखा।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि श्रमिकों को संबल प्रदान करना है। इसके तहत पात्र हितग्राहियों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है।

इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी आदि पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार भी शामिल हैं। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के देवस्थलों में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी परिवारों को भी शामिल किया गया है।

हितग्राहियों ने साझा किए लाभ

मोहला विकासखंड के ग्राम माडिंग-पिडिंग भूर्सा की हितग्राही श्रीमती शशि श्रीवास ने बताया कि शासन द्वारा संचालित यह योजना हम जैसे भूमिहीन मजदूर वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी है। इससे हमें आर्थिक संबल प्राप्त होता है, जिससे हम अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सक्षम हो पाते हैं।

ग्राम कुंजामटोला निवासी हितग्राही तीजलाल टाड़िया ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्राप्त 10 हजार रुपए की राशि का उपयोग वे अपने बच्चे की पढ़ाई-लिखाई में करेंगे। उन्होंने योजना से मिल रहे लाभ के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण में तेजी लाएं : कलेक्टर यादव

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने आज राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम मासूम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम पटेवा से पेंड्री तक निर्माणाधीन सड़क का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर स्वयं सड़क की मोटाई मापकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता का आकलन किया तथा वर्तमान प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन सड़कों को बारिश के पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों को आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने सड़क निर्माण में गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन करने तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्यों की प्रगति, उपयोग की जा रही सामग्री, लेयरिंग एवं डामरीकरण की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाने की महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्माण एजेंसी को कहा कि कार्य की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। आवश्यकतानुसार तकनीकी परीक्षण नियमित रूप से कराए जाएं।

कलेक्टर ने सड़क के सोल्डर को गुणवत्ता के साथ मजबूत बनाने के निर्देश दिए। जिससे सड़क लंबे समय तक चल सके और सड़क की टिकाऊ क्षमता बढ़ सके। साथ ही आवश्यक स्थानों पर स्पष्ट साइनेज बोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। जिससे आवागमन करने वालों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्माण क्षेत्र में उचित बैरिकेटिंग कर कार्य को पूरी तरह सुरक्षित माहौल में संचालित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि पूरे निर्माण कार्य में गुणवत्ता सर्वोपरि रहे और किसी भी चरण में मानकों से समझौता न किया जाए। कलेक्टर ने सभी निर्माणाधीन मार्गों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बारिश के पूर्व गुणवत्ता के साथ निर्माणाधीन एवं लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने ग्रामीणों से भी बातचीत कर सड़क निर्माण के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया ली। ग्रामीणों ने बताया कि नई सड़क बनने से स्कूल, बाजार, स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बारिश के मौसम में पहले आवागमन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, अब नई सड़क बनने से संपर्क सुगम हो जाएगा। कलेक्टर ने ग्रामीणों की शिकायतों और सुझावों को भी गम्भीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने उपस्थित किसानों को प्रधानमंत्री आशा योजना के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत जिले में 15 समितियों के माध्यम से दलहन एवं तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है, जिससे किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी। उन्होंने किसानों को दलहन-तिलहन क्षेत्र विस्तार के लिए प्रेरित किया तथा समय पर पंजीयन कराने कहा। निरीक्षण के दौरान पीएमजीएसवाई के कार्यपालन अभियंता पद्मसंभव मिश्रा, सहायक अभियंता सुशील सावरकर, उप अभियंता श्रीमती निधी दवे एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मोहनलाल के साथ अपनी 100वीं फिल्म करेंगे प्रियदर्शन

प्रियदर्शन ने बतौर निर्देशक 'पूचक्कोरु मूक्कुथी' से डेब्यू किया था। अब प्रियदर्शन अपनी 100वीं फिल्म लेकर आ रहे हैं। अपनी 100वीं फिल्म में प्रियदर्शन उसी अभिनेता के साथ काम करेंगे, जिनके साथ उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म की थी।

प्रियदर्शन और मोहनलाल की जोड़ी बहुत खास है, क्योंकि मोहनलाल ने प्रियदर्शन की पहली फिल्म 'पूचक्कोरु मूक्कुथी' में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। अब उनकी 100वीं फिल्म में भी मोहनलाल हीरो होंगे।

किस पर आधारित होगी फिल्म

प्रियदर्शन की 100वीं फिल्म का नाम अभी नहीं तय हुआ है। यह कॉमेडी नहीं, बल्कि एक म्यूजिकल फिल्म हो सकती है। फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने की उम्मीद है। हो सकता ही कि इस फिल्म की शूटिंग 2026 में ही शुरू हो जाए। इस फिल्म को एंटनी पेरुंबावूर की कंपनी बनाएगी। बिनु जॉर्ज अलेक्जेंडर इसके सह-निर्माता हैं।

मोहनलाल का पोस्ट

मोहनलाल ने इंस्टाग्राम पर इस फिल्म को लेकर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि यह पल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सभी लोगों का है जो इस सफर के गवाह बने। उन्होंने प्रियदर्शन को बधाई दी और कहा कि 100 फिल्में सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि जुनून, लगन और सिनेमा के जादू की पूरी जिंदगी हैं। वह इस ऐतिहासिक फिल्म का हिस्सा बनकर बहुत खुश और सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

प्रियदर्शन की डेब्यू फिल्म 'पूचक्कोरु मूक्कुथी'

साल 1984 में 'पूचक्कोरु मूक्कुथी' नाम की कॉमेडी फिल्म से प्रियदर्शन ने निर्देशक के तौर पर डेब्यू किया था। अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने मोहनलाल को हीरो चुना था। उस दिन से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में दोनों का साथ शुरू हुआ, जो अब उनकी 100वीं फिल्म तक जा पहुंचा है।

करण जौहर के 'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन का हिस्सा होंगी नेहा

करण जौहर द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन की घोषणा हो चुकी है। इसके बाद से ही लगातार दूसरे सीजन के कंटेस्टेंट को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसमें कई सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं। अभिनेत्री नेहा धूपिया के भी 'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आने की चर्चाएं थीं। अब अभिनेत्री ने खुद इन चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है और सच्चाई बताई है।

करण जौहर के शो का हिस्सा नहीं हैं नेहा धूपिया

'द ट्रेटर्स' के दूसरे सीजन में बतौर कंटेस्टेंट अपने नाम को लेकर चल रही अफवाहों पर नेहा धूपिया ने विराम लगा दिया है। नेहा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करके इस मामले को स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा, 'न तो मैं 'ट्रेटर' हूं और न ही 'इन्नोसेंट'। मैं बस डबल डेट पर जाने में व्यस्त हूं। जल्द आ रहा है।'

अपनी पोस्ट के जरिए नेहा ने न सिर्फ करण जौहर के शो का हिस्सा होने से इनकार किया, बल्कि एक आगामी प्रोजेक्ट की ओर भी इशारा किया। हालांकि, उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन उनकी पोस्ट ने प्रशंसकों के बीच उत्सुकता जगा दी है।

राजस्थान में चल रही शो की शूटिंग

'द ट्रेटर्स' की शूटिंग फिलहाल राजस्थान में चल रही है। कई मशहूर हस्तियों के नाम संभावित प्रतियोगियों के तौर पर ऑनलाइन सामने आ रहे हैं। नेहा का नाम भी शो में शामिल होने की अफवाहों में था। लेकिन फिलहाल अब नेहा धूपिया ने इस शो का हिस्सा होने से साफ इनकार कर दिया है।

चर्चा में है इन हस्तियों का नाम

'द ट्रेटर्स' के संभावित कंटेस्टेंट में कई हस्तियों के नाम चर्चा में बने हुए हैं। इनमें लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री क्रिस्टल डिसूजा कथित तौर पर 'द ट्रेटर्स' में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके अलावा रिया चक्रवर्ती, शालिनी पासी, मुनव्वर फारूकी और मल्लिका शेरावत इस सीजन के बड़े नामों में शामिल हैं। यूट्यूब पर्सनैलिटी फुकरा इंसान (अभिषेक मल्हान) और कॉमेडियन कुल्लू का भी नाम शामिल है।

उर्फी जावेद और निकिता लूथर ने जीता था पहला सीजन

शो का पहला सीजन अमेजन प्राइम वीडियो इंडिया पर प्रसारित हुआ था। पहला सीजन अभिनेत्री-फैशनिस्टा उर्फी जावेद और पोकर खिलाड़ी निकिता लूथर ने संयुक्त रूप से जीता था। करण जौहर ने पहले सीजन को होस्ट किया था। अब दूसरे सीजन को भी वो ही होस्ट करेंगे।

धुरंधर 2 फिल्म सिर्फ सीक्वल नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है, हर फ्रेम युद्ध के नगाड़े जैसा

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर : द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। अब 'कांतारा' के लिए नेशनल अवॉर्ड जीत चुके एक्टर ऋषभ शेट्टी ने फिल्म देखने के बाद आदित्य धर के विजन की जमकर तारीफ की है। ऋषभ ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर फिल्म की कास्ट और क्रू की तारीफ की। ऋषभ ने धुरंधर 2 को सिर्फ एक सीक्वल नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट बताया है। ऋषभ बोले- फिल्म सिर्फ सीक्वल नहीं, एक स्टेटमेंट ऋषभ शेट्टी ने अपने ङ्क (ट्विटर) अकाउंट पर लिखा कि 'धुरंधर 2' का पहला ही सीन दर्शकों को खुद से जोड़ लेता है और अंत तक बांधे रखता है। उन्होंने आदित्य धर की तारीफ करते हुए कहा, 'फिल्म का हर फ्रेम युद्ध के नगाड़े की तरह बजता है। यह सिर्फ एक सीक्वल नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है। शानदार कहानी और डिटेलिंग देखकर बहुत खुशी हुई।' ऋषभ ने फिल्म की एडिटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक की भी तारीफ की। ऋषभ शेट्टी ने फिल्म के कलाकारों- आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, रणवीर सिंह, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी के अभिनय को जबरदस्त बताया। उन्होंने सिनेमैटोग्राफर विकास नवलखा और म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत सचदेव को भी बधाई दी। इस पर आदित्य धर ने जवाब देते हुए लिखा, 'आपके मुंह से तारीफ मिलना बहुत मायने रखता है। मैं खुद 'कांतारा' का बहुत बड़ा फैन हूं, इसलिए आपके शब्द मेरे लिए बेहद स्पेशल हैं।'

एक बार फिर हॉरर का डोज देंगे अजय देवगन? इस निर्देशक से मिलाया हाथ

अजय देवगन इन दिनों अपनी आगामी फिल्मों 'दृश्यम 3' और 'गोलमाल 5' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बीच उनकी एक और आगामी फिल्म को लेकर दिलचस्प खबर सामने आई है। अजय देवगन एक बार फिर हॉरर की दुनिया में वापसी करने वाले हैं। अजय देवगन एक बार फिर हॉरर फिल्म में नजर आएंगे। इसके लिए उन्होंने 'सरदारजी' फ्रेंचाइजी के निर्देशक रोहित जुगराज के साथ हाथ मिलाया है।

अजय देवगन 'भूत' (2003) और 'काल' (2005) जैसी हॉरर फिल्मों में दर्शकों का मनोरंजन कर चुके हैं। अब कथित तौर पर एक्टर एक बार फिर हॉरर मूवी में नजर आएंगे। पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, अजय देवगन ने हॉरर फिल्म के लिए रोहित जुगराज के साथ हाथ मिलाया है। फिलहाल मेकर्स इस प्रोजेक्ट के प्री-प्रोडक्शन में व्यस्त हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत हैं और फिलहाल वे इसे एक हाई कॉन्सेप्ट के रूप में बनाने की तैयारी में हैं।

कास्टिंग पर चल रहा है काम

फिलहाल प्रोजेक्ट का नाम तय नहीं है। कहा जा रहा है कि इसमें एक बोल्ड, हाई-कॉन्सेप्ट वाली डरावनी कहानी दर्शकों को देखने को मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्र ने कहा कि यह फिल्म पारंपरिक हॉरर फिल्मों से अलग होगी। फिल्म की शूटिंग बड़े पैमाने पर लंदन में होगी। फिल्म के लिए कास्टिंग का काम भी चल रहा है। टीम ऐसे कलाकारों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है, जो अजय देवगन की दमदार ऑन-स्क्रीन मौजूदगी को और भी निखार सकें।

अजय देवगन 'भूत' के बाद वापसी कर रहे हैं

हॉरर जॉनर में अजय देवगन की वापसी की खबर ने दर्शकों को उत्साहित कर दिया है। हालांकि, मेकर्स की तरफ से अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स की मानें तो जुलाई से फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। अजय देवगन के वर्क फ्रंट की बात करें तो वे इन दिनों 'गोलमाल 5' की शूटिंग में व्यस्त हैं। यह फिल्म साल 2027 में दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

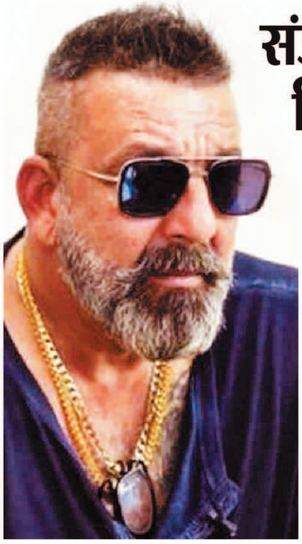

संजय दत्त की 'आखिरी सवाल' 15 मई को होगी रिलीज, सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'वन' खिसकी आगे

एक तरफ जहां संजय दत्त की नई फिल्म 'आखिरी सवाल' की रिलीज डेट सामने आ गई है, वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर 'वनः फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की रिलीज आगे खिसक गई है। अब वन की रिलीज डेट पर 'आखिरी सवाल' आएगी और 'वन' 28 अगस्त को रिलीज होगी।

'धुरंधर 2' में चौधरी असलम के किरदार से गर्दा उड़ाने के बाद संजय दत्त अब नई फिल्म 'आखिरी सवाल' में नजर आएंगे, जिसका नया पोस्टर सामने आया है। साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान किया गया है। दूसरी ओर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर 'वन : फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की नई रिलीज डेट भी सामने आई है। पहले यह फिल्म 15 मई को थिएटर्स में आने वाली थी, पर अब यह आगे खिसका दी गई है। अब इसकी जगह 15 मई को संजय दत्त की 'आखिरी सवाल' रिलीज होगी। यहां दोनों फिल्मों की कहानी और रिलीज डेट से जुड़ी सारी जानकारी दे रहे हैं:

'आखिरी सवाल' के नए पोस्टर में संजय दत्त

सबसे पहले बात 'आखिरी सवाल' की। फिल्म की पहली झलक सामने आने के बाद से ही फैंस के बीच इसे लेकर खलबली मच नए पोस्ट और रिलीज डेट ने तहलका मचा दिया है। 'आखिरी सवाल' 15 मई को थिएटर्स में रिलीज होगी। इसे नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्ममेकर अभिजीत मोहन वारंग ने डायरेक्ट किया है। 'आखिरी सवाल' में आजादी से पहले के दौर की अनकही सच्चाइयों को पहली बार दिखाया जाएगा। 'आखिरी सवाल' के पोस्टर में उस गंभीरता और विषय की सही झलक है, जिसे फिल्म में दिखाया जाएगा। एक बड़े 'क्वेश्चन मार्क' के बीच संजय दत्त का संजीदा चेहरा इस पोस्टर को काफी दिलचस्प बना रहा है, जिससे फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। इसकी टैगलाइन इसे और भी दमदार बनाती है, और वो है- वो सवाल जो भारत ने पूछना कभी बंद नहीं किया। यह अपने आप में इशारा करता है कि फिल्म एक ऐसे विषय पर आधारित है, जिससे भारत लंबे समय से जूझ रहा है।

'आखिरी सवाल' में ऋस्स के सफर की भी कहानी इसके अलावा, 'आखिरी सवाल' दर्शकों के सामने भारत के सबसे पुराने और एकजुट संगठनों में से एक- RSS के 100 साल के सफर की सच्ची कहानी भी बताएगी। इसकी स्थापना साल 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। दर्शकों को एक ऐसी महत्वपूर्ण मीटिंग देखने को मिलेगी, जिसने भारत के भविष्य को बदल दिया। यह फिल्म इतिहास की उन कहानियों से कहीं आगे जाएगी, जो हमारी किताबों में भी नहीं मिलतीं। यह राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा के मूल विचार पर रोशनी डालती है और दर्शकों को उन सच्चाइयों से रूबरू कराने का वादा करती है जो अब तक अनकही और अनदेखी रही हैं।

'आखिरी सवाल' की कास्ट

'आखिरी सवाल' में संजय दत्त के अलावा अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, समीरा रेड्डी, त्रिधा चौधरी और नीतू चंद्रा जैसे स्टार्स हैं। जबकि प्रोड्यूसर निखिल नंदा और संजय दत्त हैं।

सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'वन' 28 अगस्त को होगी रिलीज

अब बात सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की 'वन : फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट की' की। यह एक फोक थ्रिलर है, जो पहले 15 मई को रिलीज होने वाली थी, पर अब 28 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर थिएटर्स में दस्तक देगी। इसकी जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ङ्क पर एक ट्वीट में दी है। 'वन' को अङ्कस्र के अरुणाभ कुमार और दीपक मिश्रा ने डायरेक्ट किया है। वहीं, प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मॉम शोभा कपूर हैं। 'वन' की कहानी प्राचीन लोक कथाओं और भारत के मंदिरों पर आधारित बताई जाती है। फिल्म की शूटिंग रियल लोकेशंस पर की जा रही है, जिसमें मध्य भारत के घने जंगल भी शामिल हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता परखने उतरे अधिकारी — कलेक्टर, एसएसपी और डीएफओ ने किया पीएम श्री विद्यालयों का निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

जिले में पीएम श्री विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं को परखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी स्वयं विद्यालयों में पहुंचे और निरीक्षण किया। कलेक्टर से लेकर पुलिस प्रमुख और वन विभाग आला अधिकारी तक — सभी ने मैदान में उतरकर शिक्षा व्यवस्था का सीधा जायजा लिया।

केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम श्री योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य नोडल अधिकारी (SNO-PM SHRI) नियुक्त किया है। इस क्रम में सूरजपुर जिले से कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर एवं डीएफओ डीपी साहू को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सूरजपुर विकासखंड अंतर्गत पीएम श्री जयनगर का निरीक्षण कलेक्टर एस. जयवर्धन ने किया। उन्होंने विद्यालय में सेचुरेशन के 24 निर्धारित बिंदुओं की बारीकी से समीक्षा की, कमियों को चिन्हित किया और प्राचार्य को आवश्यक सुधार हेतु स्पष्ट निर्देश दिए।

इसी क्रम में सूरजपुर विकासखंड के पीएम श्री प्राथमिक शाला राजापुर का निरीक्षण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ठाकुर ने किया। ओड़गी विकासखंड अंतर्गत पीएम श्री सेजस ओडगी का निरीक्षण डीएफओ डीपी साहू ने किया।

जिले के कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व डीएफओ का विद्यालय निरीक्षण हेतु स्वयं पहुंचना प्रशासन की शिक्षा के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तीनों विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान डीएमसी समग्र शिक्षा मनोज कुमार साहू, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर हरेंद्र सिंह, खंड स्रोत समन्वयक मनोज मंडल एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित 50वीं ढफ्अत्र्क्षअळक बैठक में पीएम श्री विद्यालयों के निरीक्षण हेतु संयुक्त सचिव स्तर एवं उससे वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित करने के निर्देश दिए गए थे। उसी के अनुपालन में यह निरीक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयनित इन विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब, अटल टिंकरिंग लैब एवं बेहतर खेल सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण एवं अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिला प्रशासन के इस निरीक्षण अभियान का उद्देश्य इन विद्यालयों को आसपास के स्कूलों के लिए रोल मॉडल के रूप में स्थापित करना है।

खास खबर

1,000 से अधिक छोटे दुकानदारों को राहत दिलाने की मांग — इस्पात मंत्रालय तक पहुंचा चेम्बर का संघर्ष

भिलाई। भिलाई स्टील सिटी चेम्बर ऑफ कामर्स एवं टीम CAIT भिलाई के अथक प्रयासों के फलस्वरूप, भिलाई इस्पात संयंत्र प्रशासित क्षेत्र के लीज नवीनीकरण प्रकरण में दुकानदारों को भेजे जा रहे बेदखली नोटिसों का मामला अब सीधे केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के स्तर पर पहुंच गया है। नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड (NTWB), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के चेयरमैन सुनील जे. सिंघी ने 25 मार्च को इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक, क्अर को पत्र लिखकर इस मामले में तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

अमर परवानी की महत्वपूर्ण भूमिका : इस पूरे प्रकरण में NTWB के बोर्ड सदस्य एवं CAIT के वरिष्ठ नेता अमर परवानी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। श्री परवानी ने न केवल NTWB चेयरमैन सुनील जे. सिंघी की छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान उनसे सीधे भेंट कर यह मामला उनके संज्ञान में लाया, बल्कि NTWB की साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी इस विषय को प्रमुखता से उठाया। उनके सतत प्रयासों एवं पैरवी के कारण ही यह मामला NTWB के माध्यम से औपचारिक रूप से इस्पात मंत्रालय तक पहुंचाया जा सका। श्री परवानी ने 24 मार्च को NTWB चेयरमैन को पत्र लिखकर लगभग 1,000 छोटे दुकानदारों की पीड़ा से अवगत कराते हुए तत्काल अंतरिम राहत प्रदान करने का आग्रह किया।

मामले के मुख्य तथ्य : भिलाई टाउनशिप के लगभग 1,000 छोटे दुकानदार इस प्रकरण से सीधे प्रभावित हैं और उनके परिवारों सहित लगभग 10,000 व्यक्तियों की आजीविका दांव पर है। ये दुकानदार वर्षों से उन्हीं परिसरों में व्यवसाय एवं निवास कर रहे हैं और यह उनकी आजीविका का एकमात्र आधार है। 2008 की बोर्ड नीति की समीक्षा संबंधी कई अभ्यावेदन सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन हैं और मामला अभी अंतिम रूप से निर्णीत नहीं हुआ है। इसके बावजूद भिलाई इस्पात संयंत्र प्रशासन द्वारा बेदखली नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

ज्ञानचंद जैन के अथक प्रयास : कैट छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं भिलाई स्टील सिटी चेम्बर के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन इस आंदोलन की रीढ़ रहे हैं। उन्होंने जमीनी स्तर पर दुकानदारों को संगठित कर उनकी समस्याओं को सुव्यवस्थित रूप से प्रशासन एवं सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। श्री जैन ने चेम्बर की ओर से NTWB को लिखे गए पत्र में स्पष्ट किया कि ये दुकानदार केवल व्यवसायी नहीं, बल्कि अपने परिवारों के साथ इन्हीं परिसरों में वर्षों से निवासरत हैं। उनकी यह पहल ही CAIT एवं NTWB तक मामला पहुंचाने का आधार बनी।

कैट भिलाई के अध्यक्ष सुरेश रत्नानी ने कहा —"जब तक लंबित अभ्यावेदनों पर समुचित विचार कर कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। ऐसा करने से प्रभावित व्यक्तियों में विश्वास बना रहेगा तथा न्याय एवं समानता के सिद्धांतों का संरक्षण होगा।" चेम्बर अपने सभी सदस्यों से अनुरोध करती है कि किसी भी प्रकार का नोटिस या सूचना प्राप्त होने पर तुरंत चेम्बर कार्यालय को सूचित करें।

वेदों के बिना भारतीय शिक्षा अधूरी – डॉ. शर्मा

रानीतराई महाविद्यालय में महेशचन्द्र का रोचक व्याख्यान, रोजगार मार्गदर्शन भी दिया

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

"ज्ञान – विज्ञान की प्रतिभा में रत भारत इसकी वर्षा भी पूरी दुनिया में करता है, इसलिये भारतवर्ष भी कहलाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने स्वयं को और सारे विश्व को जगाया इसलिये भारतवर्ष जगद्गुरु के नाम से जाना गया। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता और कालिदास के बिना भारत, भारत नहीं है। इन्हीं सब के कारण पूरे संसार में भारत की प्रतिष्ठा है।" ये विचार हैं वरिष्ठ शिक्षाविद एवं पूर्व प्राचार्य डॉ.महेश चन्द्र शर्मा के। आचार्य डॉ. शर्मा विगत दिनों स्व.दाऊ रामचन्द्र साहू शा.महाविद्यालय रानीतराई में 'भारतीय ज्ञान परम्परा एवं वैदिक संस्कृति' विषय पर शिक्षाविदों और विद्यार्थियों को विशेषज्ञ मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे।

देश–विदेश के अनेक सफल शैक्षणिक भ्रमण कर चुके आचार्य डॉ.शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भारतीय ज्ञान परम्परा के सन्दर्भ में बताया कि वैदिक साहित्य के सार के रूप में उपनिषद् कहता है – असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने का काम करे वही सच्ची शिक्षा है। डॉ. शर्मा ने बताया कि शिक्षा नीति रोजगार को भी महत्त्वपूर्ण मानती है। उन्होंने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन सहित रोजगार पठन–पाठन सामग्री भी दीं। साथ ही पर्यावरण अध्ययन फाइल सामग्री भी दीं। आचार्य शर्मा ने शिक्षा नीति से प्रेरित स्वरचित अपनी चार पुस्तकें – प्रेरणा प्रदीप, साहित्य और समाज, छत्तीसगढ़ में संस्कृत और गागर में सागर आदि भी प्राचार्य डॉ.मिश्र और ग्रन्थालय को निः शुल्क भेंट कीं। महाविद्यालय के प्राचार्य एवं गणितज्ञ डॉ. अरुण कुमार मिश्र ने व्याख्यान की भूमिका रखते हुवे विषय और विशेषज्ञ के बारे में भी बताया।

उन्होंने महाविद्यालय की ओर से आचार्य डॉ.शर्मा का शॉल–श्रीफल से अभिनंदन किया। आईक्यूएसी प्रभारी एवं संयोजक चन्दन गोस्वामी एवं आईकेएस प्रभारी और सहसंयोजक अम्बिका ठाकुर बर्मन ने अपनी भूमिकाओं का सफल निर्वाह किया। कार्यक्रम का सफल संचालन आराधना देवांगन और आभार ज्ञापन अम्बिका ठाकुर बर्मन ने किया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) द्वारा प्रायोजित और आईकेएस द्वारा आयोजित व्याख्यान में डॉ. रेशमी वासनीकर, भारती गायकवाड, डॉ.शगुफ़्ता सिद्दीकी एवं रेणुका वर्मा समेत बड़ी संख्या में स्टाफ एवं विद्यार्थी गण उपस्थित रहे।

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मिली लाश

भिलाई। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 42 वर्षीय युवक मोहन रामटेक की संदिग्ध हालात में शव मिली है। घर में फंदे से लटका शव मिलने के बाद जहां पुलिस इसे आत्महत्या के एंगल से जांच रही है, वहीं मृतक के भाई नवीन रामटेके ने हत्या की आशंका जताई है। परिवार का कहना है कि शव पर चोट के निशान भी मिले हैं और सुसाइड नोट में दो लोगों के नाम सामने आए हैं, जिससे मामला संदिग्ध हो गया है। जानकारी के अनुसार मोहन रामटेक पिछले करीब 3 महीनों से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था और पेंटिंग का काम करता था। शानिवार सुबह मकान मालिक को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के अंदर फंदे से लटका शव बरामद किया और सुसाइड नोट जब्त किया। मृतक के भाई नवीन रामटेके ने बताया कि किसी से कोई बड़ा विवाद सामने नहीं आया था, लेकिन शरीर पर चोट के निशान मिलने से हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

निधन

सुमित्रा बाई साहू

राजनांदगांव। जनपद पंचायत के सहायक ग्रेड–3 अधिकारी अखिलेश साहू की धर्मपत्नी श्रीमती सुमित्रा बाई साहू का 28 मार्च को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार दोपहर 1 बजे देवरसुर (मोहला) में किया गया। शोकसभा में पूर्व जनपद सदस्य योगेंद्र दास वैष्णव, राजनांदगांव संरक्षक, जनपद पंचायत राजनांदगांव, सरपंच सिघोला मुकेश कुमार साहू, उपाध्यक्ष सरपंच संघ, ढोडिया सरपंच दिल्लू साहू, कोटराभांटा सरपंच डान साहू, सरपंच प्रतिनिधि गौरी कृतलाल पटेल, धामनसरा जनपद सदस्य मोहला, श्रीमती अनिता जसवाल, सरपंच प्रतिनिधि देवकुमार साहू, पूर्व सरपंच देवरसुर द्वारिका शोरी सहित साहू समाज के पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधान आरक्षक मुकेश व उसकी पत्नी पूनम के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध

नई दृष्टिबिंदु / रायगढ़

न्यायिक मजिस्ट्रेड प्रथम श्रेणी पुनीत समीक्षा खलखो ने रायगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पूर्व में कार्यरत प्रधान आरक्षक मुकेश त्रिपाठी व उसकी पत्नी पूनम त्रिपाठी के खिलाफ 294, 506, 500, सहपठित धारा 511 एवं सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करने के आदेश जारी किये हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेड प्रथम श्रेणी पुनीत समीक्षा खलखो ने यह आदेश मंजु अग्रवाल द्वारा पांच साल पहले दायर एक परिवाद पत्र के आदेश की सुनवाई के बाद जारी किया है।

बीते पांच साल से महिला न्याय के लिये लगातार प्रयास कर रही थी और समस्त गवाह एवं सबूतों के आधार पर न्यायलय द्वारा सुनवाई के बाद प्रधान आरक्षक मुकेश त्रिपाठी व उसकी पत्नी पूनम त्रिपाठी के खिलाफ 294, 506, 500, सहपठित धारा 511 एवं सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करने के आदेश जारी किये हैं। वतर्मान में मुकेश त्रिपाठी राजधानी रायपुर स्थित एसीबी कार्यालय में कार्यरत हैं। इस मामले की पैरवी अधिवक्ता सिराजुद्दीन ने की थी।

अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार बीते 3 नवंबर 2020 को परिवादिनी जब कोतरा रोड स्थित सावित्री नगर में मुकेश त्रिपाठी के घर अपने पति को घर बुलाने के लिये गई थी इसी दौरान मुकेश त्रिपाठी व उसकी पत्नी पूनम त्रिपाठी ने परिवादिनी मंजु के खिलाफ अश्लील गालियां बकते हुए उसे सार्वजनिक तौर पर अपमानित करते हुए धमकी भी दी थी और इतना ही नही इस घटना के बाद मुकेश त्रिपाठी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उसी दिन परिवादिनी के खिलाफ कई धाराओं के तहत सिटी कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कराते हुए धमकियां जारी रखी थी। इस दौरान परिवादिनी ने अपने साथ होनें वाले अन्याय की गुहार 3 नवंबर 2020 को सिटी कोतवाली में लिखित आवेदन के जरिये लगाई थी लेकिन मुकेश त्रिपाठी के दबाव से सिटी कोतवाली द्वारा शिकायत पर कार्रवाई करना तो दूर उल्टे ही पीड़िता को धमकाना व प्रताडित करना जारी रखा था। इतना ही नही सामाजिक व परिवारिक रूप से भी लगातार उसका भयादोहन किया जाता रहा।

इस परिवाद पत्र की सुनवाई के बाद सम्मानीय न्यायालय द्वारा बीते 12 मार्च 2026 को पूरी सुनवाई के बाद प्रधान आरक्षक मुकेश त्रिपाठी व उसकी पत्नी पूनम त्रिपाठी के खिलाफ 294, 506, 500, सहपठित धारा 511 एवं सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करने के आदेश जारी किये हैं और अपने आदेश में न्यायिक मजिस्टेज्ड प्रथम श्रेणी पुनीत समीक्षा खलखो ने समस्त धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करने के आदेश जारी करते हुए आरोपीगण को 16 अप्रैल को न्यायालय में उपस्थित होनें को कहा है।

बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए नया सब-स्टेशन ऊर्जीकृत

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी निरंतर और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिए दुर्ग जिला में पारेषण क्षमता का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में धमधा ब्लॉक के लिटिया – सेमरिया गांव में 220/132/33 केवी के नए उपकेन्द्र का निर्माण किया गया है, जिसकी क्षमता 160 एमवीए है। इसे ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने बटन दबाकर ऊर्जीकृत किया। इस क्षमता विस्तार से दुर्ग व धमधा ब्लॉक क्षेत्र के 150 से अधिक गांव के विद्युत उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हो सकेगी।

इस अवसर पर श्री शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह के निर्देशन में प्रदेश में पारेषण नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। इसमें क्षेत्र में पंजीगत निवेश के तहत कार्य कराए जा रहे हैं। इसी के तहत लिटाया सेमरिया में 132/33 के.वी. के नए उपकेंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें 40–40 एमवीए के दो पॉवर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इसकी अनुमानित लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। इस उपकेंद्र से 33 केवी के 6 फीडर से बिजली सप्लाई होगी।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक संजय पटेल, एस.सलेट, ए.एम. परियल, मुख्य अभियंता अब्राहम वर्गीश, अतिरिक्त मुख्य अभियंता पी .पी. सिंग, अधीक्षण अभियंता राजेश तिवारी, राजेंद्र कुमार मिश्रा, एस. के. भुआर्य, कार्यपालन अभियंता धर्मेंद्र भारती, छगन शर्मा, डी.के.साहू, श्रीमती बरखा दुबे, एस.सिन्नी, सिद्धार्थ भावसार सहित अन्य अधिकारी/कमर्चारी उपस्थित रहे। इस उपलब्धि से दुर्ग जिले के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, साथ ही औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

वाणिज्य, उद्योग व श्रम मंत्री देवांगन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निर्मित रैन बसेरा का किया लोकार्पण

नई दृष्टिबिंदु / कोरबा

वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखन लाल देवांगन द्वारा आज कोरबा स्थित स्व. श्री बिसाहू दास महंत स्मृति मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एसईसीएल के सीएसआर मद से 61.82 लाख रुपये की लागत से निर्मित सवर्सुविधायुक्त आश्रयालय का लोकार्पण किया।

कार्यक्रम में मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को 4.50 करोड़ रुपये की अत्याधुनिक जांच मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि 50 बिस्तर क्षमता वाला क्रिटिकल केयर यूनिट 16.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन है, जो शीघ्र ही पूर्ण होगा। इसी प्रकार कैजुअल्टी भवन के ऊपरी तल पर 100 बिस्तरों वाले नए वार्ड का निर्माण लगभग 3 करोड़ रुपये में जारी है। गर्मी से मरीजों व परिजनों को राहत दिलाने के उद्देश्य से अस्पताल में 83 एयर कंडीशनर लगाए जा रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि 40 बिस्तरों की क्षमता वाला आई वार्ड लगभग 1 करोड़ 21 लाख रुपये की लागत से जल्द प्रारंभ किया जाएगा। नवजात शिशुओं हेतु 6 बिस्तरों का विशेष वार्ड तैयार किया गया है। साथ ही सीएसआर एवं डीएमएफ फंड से सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन की खरीद की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जिसके बाद जिलेवासियों को अत्याधुनिक उपचार सुविधाएँ मिलेंगी। उन्होंने कहा कि नए आश्रयालय (रैन–बसेरा) के शुरू होने से मरीजों के परिजनों को ठहरने में अब किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ समय पर उपलब्ध हों।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने कहा कि सुशासन की सरकार एवं केबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों में कोरबा में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति दर्ज की गई है। इस अवसर पर सभापति श्री नूतन ठाकुर तथा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन डॉ. केके सहारे उपस्थित रहे।

गोवा के मंत्री डॉ. तावड़कर ने देखी छग जनजातीय गौरव की एक झलक

सांस्कृतिक आदान–प्रदान, शोध व विकास के लिए गोवा और छत्तीसगढ़ के मध्य होगा एमओयू

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

गोवा राज्य के जनजातीय विकास, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री डॉ. रमेश तावड़कर ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति और गौरव की झलक देखी। उन्होंने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय एवं शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का भ्रमण कर जनजातीय कला, संस्कृति, रीति–रिवाज एवं जनजातीय शौर्य के जीवंत प्रदर्शन को देखकर वे अत्यंत प्रभावित हुए।

गोवा के जनजातीय विकास मंत्री डॉ. तावड़कर ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। संग्रहालय में जनजातीय शौर्य के जीवंत प्रदर्शन एवं बड़े पैमाने पर किए गए डिजिटलीकरण ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि गोवा राज्य में भी जनजातीय समुदाय का समृद्ध इतिहास रहा है, परन्तु छत्तीसगढ़ की तरह इसका व्यापक प्रचार–प्रसार नहीं हो पाया है। इस मौके पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण करते हुए कहा कि वर्ष 2003 में उनके कायर्काल के दौरान ही गोवा में निवासरत जनजातीय समुदाय को पहली बार औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई थी।

डॉ. तावड़कर ने कहा कि गोवा एवं छत्तीसगढ़ के मध्य जनजातीय शोध, विकास एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में बेहतर आदान–प्रदान की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधिमंडल को गोवा भ्रमण हेतु आंमत्रित भी किया। इस मौके पर गोवा राज्य के संचालक खेल डॉ. अजय कुमार गोड़े, आदिम जाति विभाग गोवा के संचालक निलेश डाऐगोडकर, संचालक टीआरआई गोवा पी. गांओकर, ओएसडी राजेन्द्र बोरकर, वरिष्ठ अधिकारी अर्जुन रामकृष्ण पाटिल, जनक टेकाले, मृकुंद नायक तुब्की, अशोक अरविन्द काले एवं राजेन्द्र दताजीराव भी मौजूद थे।

संग्रहालय भ्रमण के उपरांत टीआरआई के सभागार में एक संक्षिप्त बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें दोनों राज्यों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा द्वारा पीपीटी के माध्यम से दोनों संग्रहालयों के निर्माण कार्य, उनकी विशेषताओं एवं उपलब्धियों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि गोवा एवं छत्तीसगढ़ के मध्य शीघ्र ही एक एमओयू किया जाएगा, जिससे जनजातीय संग्रहालय निर्माण, जनजातीय शोध, विकास सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग स्थापति हो सकेगा। बैठक में संस्थान की संचालक श्रीमती हिना अनिमेष नेताम ने जनजातीय संस्कृति के क्षेत्र में बन रहे ट्राईबल फोक म्यूजिक स्टूडियो सुरगुड़ी पर जानकारी दी।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय शौर्य को प्रदर्शित करता शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का लोकार्पण राज्योत्सव के समय 01 नवंबर 2025 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर कमलों से हुआ था, जबकि छत्तीसगढ़ अदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण मई 2025 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कर कमलों से हुआ। इनके लोकार्पण के बाद इन्हें आमजन हेतु खोल दिया गया है। अब तक लगभग 02 लाख से अधिक पर्यटकों, शोधार्थियों, विशेषज्ञों द्वारा इसका भ्रमण किया जा चुका है।

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, 2026 के अवसर पर आयोजित परेड में शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय की प्रतिकृति को प्रदर्शित किया गया। इससे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में जनजातीय वीर नायकों की अमर गाथाओं, उनकी देश भक्ति, अदम्य साहस और बलिदान की परंपरा को नई पीढ़ी को जानने समझने का अवसर राष्ट्रीय मंच पर प्राप्त हुआ।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग

–:: ईश्तहार::–

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय का रा.प्र.क्र. 202603101000160/अ–6/वर्ष 2025–26 में आवेदिका/आवेदक रामनाथ जंघेल आ. /ध.प. स्व. जीवराखन राम संघल निवासी आर्य नगर कोहका तह. दुर्ग व जिला दुर्ग द्वारा ग्राम कोहका प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. कोहका व जिला दुर्ग स्थित भूमि व स्वामी हक की भूमि खसरा नं. 546 रकबा 0.02 हे. है। जो भूमिस्वामी जीव राखन राम जंघेल आ. दीनदयाल के नाम पर दर्ज है। जिसमें भूमिस्वामी जीवराखन राम जंघेल की मृत्यु दिनांक 01/09/2020 को फौत हो जाने के कारण मृतक का नाम खाते से विलोपित कर उसके वैध वारिसानो का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त भूमि फौती नामांतरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 16/04/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24/03/2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन दिल्ली बुलाए गए, छग से चयनित विधायकों के साथ होंगे रवाना

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

जनप्रतिनिधियों को डिजिटल संचार के आधुनिक तरीकों और गवर्नेंस टूल्स से लैस करने के उद्देश्य से 30 मार्च को दिल्ली में आयोजित बहुपयोगी वर्कशॉप में छत्तीसगढ़ के 5 विधायकों को शामिल किया गया है। हाल ही में एनएफपीआरसी के चेयरमैन तरुण चुघ ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को पत्र लिख 5 विधायकों को इस कार्यशाला के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया था जिसमें वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन भी शामिल हैं।

नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर द्वारा नई दिल्ली के एम्बेसडर होटल में 'डिजिटल संचार और सार्वजनिक शासन उपकरणों के माध्यम से विधायी प्रभाव को बढ़ाना' विषय पर आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यशाला में छत्तीसगढ़ से चयनित विधायकों में वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। आपको बता दें कि यह कार्यशाला सांसदों और विधायकों को डिजिटल युग में जनता से प्रभावी ढंग से जुड़ने और सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए आधुनिक उपकरणों से लैस करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है।

विधायक रिकेश सेन ने डिजिटल संचार के माध्यम से जनता के साथ संबंध मजबूत करने और सार्वजनिक शासन उपकरणों का उपयोग करके निर्वाचन क्षेत्र के विकास को गति देने के तरीकों पर होने वाली इस कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी बताते हुए कहा कि यह जनप्रतिनिधियों के लिए अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने और जनता की सेवा करने के लिए एक मूल्यवान अवसर है।

कार्यशाला की मुख्य विशेषताएं

जनप्रतिनिधियों को डिजिटल उपस्थिति को मजबूत करने और सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग करके जनता के साथ सीधे संवाद स्थापित करने के तरीकों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें दिशा समितियों, MLALADS फंड और अन्य सार्वजनिक शासन उपकरणों के प्रभावी उपयोग पर चर्चा की जाएगी ताकि निर्वाचन क्षेत्र के विकास में तेजी लाई जा सके। इस कार्यशाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर, सांसद शशांक मणि और विदिशा के जिलाधिकारी अंशुल गुप्ता जैसे विशेषज्ञ अपने अनुभव और ज्ञान साझा करेंगे।

विधायक रिकेश सेन ने कार्यशाला के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि डिजिटल संचार आज के दौर में जनप्रतिनिधियों के लिए एक आवश्यक उपकरण है। यह हमें जनता के साथ सीधे संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। मैं इस कार्यशाला से सीखे गए कौशल और ज्ञान का उपयोग करके अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा के लिए तत्पर हूं। दुर्ग संभाग से श्री सेन के साथ दिल्ली बुलाए गए छत्तीसगढ़ के कुल 5 विधायकों में रायपुर संभाग से अनुज शर्मा धरसींवा, सरगुजा संभाग से श्रीमती गोमती साय पत्थलगांव, बस्तर संभाग से चैतराम अटामी दंतेवाड़ा तथा विधायक राजिम रोहित साहू भी शामिल हैं।

अशोक कुमार पांडा बने सेल के नए चेयरमेन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

अशोक कुमार पांडा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL नए चेयरमैन होंगे आज संपन्न साक्षात्कार के उपरांत अशोक कुमार पांडा को सेल अध्यक्ष के लिए उपयुक्त मानते हुए उनके नाम को हरी झंडी दे दी गई भिलाई स्टील प्लांट में सेवाएं दे चुके अशोक कुमार पांडा को स्टील के क्षेत्र में एक अनुभवी बेहतरीन अधिकारी के रूप में पहचाना जाता है। साक्षात्कार में अशोक कुमार पांडा सहित 10 अधिकारी शामिल हुए थे।

फिरोज ने खेलमंत्री संग खिलाड़ियों को किया सम्मानित

नई दिल्ली । हॉकी जगत का प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया अवार्ड्स का आयोजन किया गया। हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मांडविय के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। समारोह में भारतीय पुरुष एवं महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए करोड़ों रुपये के नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर फिरोज अंसारी, जो हॉकी इंडिया के सह-सचिव एवं छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष हैं, ने खेल मंत्री के साथ मंच साझा किया और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में भारत के महान हॉकी खिलाड़ी अजित पाल सिंग की गरिमामयी उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। पूर्व महान खिलाड़ी जफर इक़बाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के साथ 25 लाख का नगद पुरस्कार दिया गया उनके हाथों अजीत पाल सिंह मिडफील्डर अवार्डह्व भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी सुमित कुमार को प्रदान किया गया। इस भव्य आयोजन ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के मनोबल को नई ऊंचाई प्रदान की।

एफएसएनएल के सैकड़ों श्रमिकों पर बेरोजगारी का संकट, 30 को मुर्गा चौक पर होगी बड़ी स्ट्राइक

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के सैकड़ों श्रमिकों पर रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रमुख नियोक्ता होने के बाद भी भिलाई स्टील प्लांट द्वारा एफएसएनएल को काम देने के बजाय ग्लोबल टेंडर निकाला गया। चार टुकड़ों में निकाले गए इस टेंडर के कारण एफएसएनएल के हिस्से में जो काम आया वह यहां कार्यरत 800 से ज्यादा श्रमिकों के लिए पर्याप्त नहीं है। भिलाई इस्पात संयंत्र की इस नीति के खिलाफ FSNL बचाओ संघर्ष समिति मोर्चा खोला गया है। समिति के बैनर तले मुर्गाचौक सेक्टर-1 पर 30 मार्च को हड़ताल होगी जिसमें सभी प्रभावित श्रमिक शामिल हो रहे हैं।

इस संबंध में संयोजक मंडल के सदस्य गजेन्द्र सिंह, राजु लाल श्रेष्ठ, एव अरुण सिंह सिसोदिया ने शनिवार को संयुक्त पत्रकार वार्ता में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि FSNL पूर्व में भारत सरकार का उपक्रम था। जो विनिवेश निति के अन्तर्गत भारत

सरकार द्वारा षड़यंत्र के तहत निजीकरण करते हुए जापानी कंपनी कोनोइके ट्रांसपोर्ट कंपनी को 320 करोड़ में दे दिया जबकि FSNL का मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ से भी अधिक था । हाल के दिनों में स्क्रैप माफियाओं द्वारा FSNL को कमजोर करने तथा समाप्त करने के लिए षड़यंत्र रचा जा रहा था। FSNL को मिलने वाले सभी टेंडर पहले एक पार्टी के सिद्धांत पर आधारित थे। जिसे ओपन टेंडर में परिवर्तित किया गया था। ओपन टेंडर के कारण 750 करोड़ का टेंडर चार भागों में बांटा गया।

संयोजक मंडल के सदस्यों ने बताया कि FSNL 1979 से 1983 तक सेल का साझेदारी कंपनी थी तथा इस्पात मंत्रालय को MSTC में शेयर ट्रांसफर किये गए जो की 60% व 40% था । उसके पश्चात 100% टरळउ को सेल को ट्रांसफर किया गया। FSNL पिछले 40 वषी से इस्पात उद्योग में स्लैग एव स्क्रैप प्रोसेसिंग मैग्नेटिक सेपरेटर का निष्पादन करता हैं। जिससे इस्पात मंत्रालय के हजारो करोड़ का शुद्ध लाभ होता हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत बीएसपी सयंत्र प्रमुख नियोक्ता की भूमिका में हैं तथा नियोक्ता के रूप में FSNL ने श्रम विभाग से लेबर लाइसेंस प्राप्त किया हैं। इसलिए प्रमुख नियोक्ता बीएसपी तथा नियोक्ता FSNL की सयुक्त जिम्मेदारी बनती हैं कि संस्थान में कार्यरत सभी नियमित तथा ठेका श्रमिकों की नौकरी, सेवाए सुनिषित करे तथा उनके वेतनमान एव सेवा शर्तो में कोई परिवर्तन न किया जाये ।

संयोजक मंडल के सदस्यों ने बताया कि जो टेंडर जनवरी में हुए हैं उक्त टेंडर में कारखाने में कार्यरत नियमित एव ठेका श्रमिकों के नौकरी तथा सेवा शर्तो के सबंध में कोई उल्लेख नहीं हैं। जबकि उक्त कार्य स्थाई प्रकृति का हैं इसलिए कार्य में नियोजित ठेका श्रमिकों को ठेका संविदा उन्मूलन अधिनियम 1970 केन्द्रीय नियम 71 की धारा 10 के अनुसार विभागीय कारण किया जाना चाहिए। कोई भी ठेकदार बदलने की स्थिती में उन्हें स्थाई उसी स्थान पर उनके पुराने वरिष्ठता सुनिश्चित करते हुए उसी स्थान पर उन्हें नियमित सेवारत किया जाना चाहिए।

संयोजक मंडल के सदस्यों ने कहा है कि हमारी मांग है नये टेंडर से श्रमिकों की सेवा निरंतर रहे तथा उनके वेतनमान तथा उनके सेवा शर्तो पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। ठेका क्रमांक 872 व स्थायी 373 हैं। ठेकेदार बदलने के कारण किसी भी ठेका श्रमिक, स्थायी श्रमिक की छटनी न किया जाए तथा न कही स्थानांतरण किया जाये। सभी ठेका श्रमिकों को नए वेज-कोड के आधार पर नियुक्त पत्र दिया जाये। केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन की भुगतान सुनिश्चित किया जाये । सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची, कानून छुट्टी जैसे एछ,उछ राष्ट्रीय अवकाश दिया जाए।

शपथ फाउंडेशन का हेल्प लाइन बन रहा है जरूरतमंदो का सहारा

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

विगत कुछ माहों से शपथ फाउंडेशन भिलाई ने अपना हेल्प लाइन जारी किया है जिसमें दिव्यागजन या फिर उनके आस पास के लोग व परिचित अपनी समस्या हेतु आगे आ कर इस हेल्प लाइन पर फोन कर अपनी समस्या और बात रख रहे है आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह हेल्प लाइन चौबीस घंटे और 365 दिन चालू रहती है।

भिलाई दुर्ग ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में दिव्यागजनों हेतु अभी तक की निजी क्षेत्र में यह अपने आप में किसी भी संस्था की यह पहली ऐसी पहल में से एक है जिसने अपनी निजी हेल्प लाइन जारी की है।

इस हेल्प लाइन का उद्देश्य जरूरतमंदों के लिए ना सिर्फ ट्राई सायकल, व्हील चेयर बल्कि साथ साथ राशन एवं उनके जरूरत अनुसार सामानों का वितरण करना है। संस्था के इस पहल में प्रबुद्ध जन साथ आगे आकर कार्य कर रहे है और शहर के लोगों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा इस पहल को सराहा जा रहा है। संस्था के संस्थापक अशोक गुप्ता ने अपील करते हुए कहा कि आपके साथ पास कालोनी, वार्ड , शहर में अगर किसी भी दिव्यांग जन को जरूरत हो तो हमारी हेल्प लाइन नंबर 9926844441 पर तुरंत संपर्क करे ,संस्था द्वारा संपर्क किए जाने के बाद जल्द से जल्द राहत पहुंचाने कि पहल किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा !

श्रीराम नवमी पर निकाली भव्य शोभायात्रा

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

सर्व हिंदू समाज विश्वहिंदू परिषद बजरंगदल मातृशक्ति ने गुजराती समाज की अगवाई में श्रीराम नवमी पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा को पूरे शहर भ्रमण कराया गया जिससे शहर का पूरा वातावरण भक्तिभाव से भर गया।

सहकारिता विभाग ने लांघा सुप्रीम कोर्ट का दायरा, इंक्रीमेंट के नाम पर खुलकर भ्रष्टाचार

शासन ने ही सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, फैसला आने के पहले आदेश जारी

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्य सहकारिता विभाग द्वारा कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देने बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देशों को मानने से इंकार कर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण लंबित हैं। जबकि जगदलपुर जिला सहकारी केन्द्रि बैंक के कमर्चारियों को इंक्रीमेंट जारी किए जाने का आदेश जारी कर शासन ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट का दायरा लांघ दिया है। प्रदेश के एक मात्र जिला सहकारी केन्द्रि बैंक जगदलपुर में राज्य शासन द्वारा जारी किए गए एकतरफ आदेश के बाद खलबली मच गई है। इस पूरे खेल में सहकारिता मंत्री के करीबी को लाभ पहुंचाने के चलते भ्रष्टाचार का खेला चल रहा है।

प्रदेश का सहकारिता विभाग आज खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। इंक्रीमेंट भुगतान के मामले में जो तथ्य सामने आए हैं, वे न केवल प्रशासनिक अराजकता बल्कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और संरक्षणवाद की ओर इशारा करते हैं। इंक्रीमेंट से संबंधित मामला पहले ही छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में कमर्चारियों के पक्ष में आ चुका है। इसके बावजूद स्वयं छत्तीसगढ़ शासन ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जहां मामला अभी भी विचाराधीन है। इस पूरे मामले में 13/11/2025 को संयुक्त आयुक्त सहकारिता, बस्तर संभाग, जगदलपुर द्वारा जारी आधिकारिक पत्र भी कई गंभीर सवाल खड़े करता है। उक्त पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि, शासन द्वारा दायर SLP (उ) 032232/2025 सवीच्च न्यायालय में लंबित है और अंतिम निर्णय के बाद ही वेतन वृद्धि एवं महंगाई भत्ते के संबंध में कार्यवाही की जाएगी।

अफसर खुद घिर रहे, मंत्री के करीबी को लाभ

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्वयं विभाग का अधिकृत पत्र यह कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही कार्रवाई होगी, तो फिर जगदलपुर जिला सहकारी बैंक में इंक्रीमेंट का भुगतान किस आधार पर और किस दबाव में किया गया? जगदलपुर बैंक के

अध्यक्ष, जो सहकारिता मंत्री के करीबी रिश्तेदार हैं, और सहकारिता मंत्री के ओएसडी तथा सहकारिता विभाग के अधिकारियों की भूमिका इस पूरे प्रकरण में गंभीर संदेह के घेरे में है। यह पूरा घटनाक्रम साफ तौर पर संकेत देता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद भुगतान कराने के पीछे भारी-भरकम लेन-देन हुआ है।

रायपुर बैंक प्रबंधक भी संशय में

इसी तरह का मामला रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में भी लंबित है, जिससे वहां के प्रबंधन के सामने बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है—क्या वे कानून और न्यायालय का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें या फिर जगदलपुर की तरह नियमों को ताक पर रखकर भुगतान कर दें? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि, सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता स्वयं सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ शासन है, और वतर्मान में भुगतान की अनुमति देने वाले भी शासन के ही सहकारिता विभाग हैं। यानी एक ही शासन दोहरी भूमिका निभा रहा है—एक ओर कोर्ट में मामला लंबित रखकर न्यायिक प्रक्रिया को उलझाना, और दूसरी ओर मनमाने तरीके से भुगतान की अनुमति देना।

लेन देन का भी लग रहा आरोप

कोर्ट में लगे याचिका के बाद फैसले के पहले इस तरह सरकार द्वारा एकतरफ जगदलपुर जिला सहकारी केन्द्रि बैंक के पक्ष में फैसला लेने से सवाल उठ रहे है। ऐसी चर्चा है कि इस जमकर लेन देन भी हुए है। यह पूरा मामला सहकारिता विभाग में खुला खेल फर्रुखाबादी का जीता-जागता उदाहरण बन चुका है। अब प्रदेश की जनता और कमर्चारी यह जानना चाहते हैं कि आखिर नियम और कानून का पालन होगा या फिर रिश्तेदारी और लेन-देन के आधार पर फैसले होते रहेंगे?

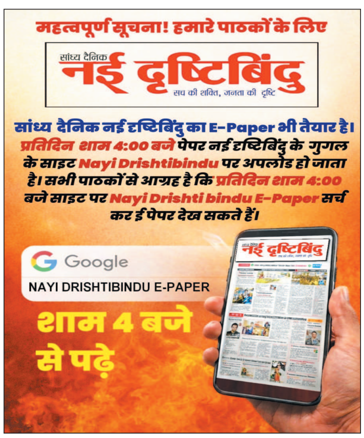

पीआरजीआई सं.-CTHIN/25/A3746 यह हिंदी सांध्य दैनिक समाचार पत्र नई दृष्टिबिंदु स्वामी एवं प्रकाशक आलोक तिवारी द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 से मुद्रित करवा कर। 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से प्रकाशित संपादक आलोक तिवारी मो. 7415469100 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारण न्यायलयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।